हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

17 मार्च, 2008

खण्ड-1, अंक-7

अधिकृत विवरण

LIBRARY

विषय सूची

सोमवार, 17 मार्च, 2008

	पृष्ठ संख्या
शोक प्रस्ताव	(7)1
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(7)2
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(7)21
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(7)28
सदन की मेज पर रखे गए कागज-पत्र	(7)30
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भ)	(7)30
वैयक्तिक स्पष्टीकरण— श्री ओम प्रकाश चौटाला द्वारा	(7)44
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भ)	(7)45
सदस्य का नाम लेना	(7)48
वाक-आऊट	(7)49
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भ)	(7)49

74

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 17 मार्च, 2008

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में दोपहर अपराह्न 2.00 बजे हुई। अध्यक्ष (डॉ० रघुवीर सिंह कादियान) ने अध्यक्षता की।

शोक प्रस्ताव

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सामने शोक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े शोक के साथ शोक प्रस्ताव सदन के सामने रख रहा हूँ। यह सदन भूतपूर्व संसद सदस्य, श्री मुख्तियार सिंह मलिक के 14 मार्च, 2008 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 3 जुलाई, 1911 को हुआ। उन्होंने देश के स्वतन्त्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे 1962 में संयुक्त पंजाब विधान सभा तथा 1968 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये। वे 1980 से 1984 के दौरान हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम के अध्यक्ष रहे। 1967 और 1984 में राज्यसभा के लिए चुने गये व 1971 एवं 1989 में लोकसभा के सदस्य रहे। उन्होंने सदा आम आदमी के उत्थान के लिए कार्य किया। वे अनेक शैक्षिक संस्थाओं से भी जुड़े रहे। आज के दिन वे हमारे हरियाणा के सबसे सीनियर राजनीतिज्ञ थे। वे मेरे पिता जी से भी ज्यादा उम्र के थे। उनके निधन से देश एक अनुभवी सांसद एवं योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

इसी प्रकार से हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो एक-एक करके हमें छोड़ कर जा रहे हैं। यह सदन जिला रिवाड़ी के गाँव माजरा श्योराज के स्वतंत्रता सेनानी श्री ओंकार सिंह के 9 मार्च, 2008 को हुए निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनके निधन से देश एक स्वतंत्रता सेनानी की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

इसी प्रकार से यह सदन जीन्द जिले के एक गाँव इगरा के वीर सैनिक श्री सूबे सिंह के 6 मार्च, 2008 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनके निधन से देश एक वीर सैनिक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

डॉ० सुशील इन्दौरा (एस०सी०, ऐलनाबाद) : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो शोक प्रस्ताव सदन के सम्मुख रखे हैं मैं भी अपने आपको उनके साथ जोड़ते हुए अपनी पार्टी तथा अपनी पार्टी के नेता की तरफ से गहरा शोक प्रकट करता हूँ तथा दिवंगतों

[डॉ० सुशील इन्दौरा]
के शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि श्री मुख्तियार सिंह मलिक, श्री ओंकार सिंह तथा श्री सूबे सिंह के शोक संतप्त परिवारों को इस दु:ख की घड़ी में इस दुख से उबरने की शक्ति प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, माननीय मुख्यमंत्री ने श्री मुख्तियार सिंह मलिक के निधन पर जो शोक प्रस्ताव रखा है और डॉ० इन्दौरा ने उनके बारे में जो अपने विचार प्रकट किये हैं, मैं भी अपने आपको उनके साथ जोड़ता हूँ। श्री मुख्तियार सिंह मलिक, दो बार लोक सभा में, दो बार राज्य सभा में तथा दो बार विधान सभा में चुन कर आये थे। वह एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के मालिक थे। उनकी रुचि न केवल खेल-कूद में तथा शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने में थी बल्कि वह एक अच्छे जनप्रतिनिधि भी थे। उनके निधन से हम सभी ने एक सच्चा समाज सेवी खो दिया है। श्री ओंकार सिंह, स्वतंत्रता सेनानी तथा श्री सूबे सिंह, वीर सैनिक के निधन पर भी मुझे गहरा शोक लगा है। श्री ओंकार सिंह ने अपनी जवानी के बहुमूल्य साल देश को अर्पित किये और श्री सूबे सिंह ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिये।

मैं परमपिता परमात्मा से इन सभी दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करने के लिए प्रार्थना करता हूँ और इन शोक संतप्त परिवारों तक इस सदन की संवेदना पहुंचा दी जायेगी। अब मैं दिवंगत आत्माओं के सम्मान में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए दो मिनट का मौन धारण करने के लिए इस सदन के सभी सदस्यों को खड़ा होने के लिए अनुरोध करता हूँ।

(इस समय सदन ने दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया।)

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Questions hour.

Divider on Circular Road, Bhiwani

***873. Dr. Shiv Shankar Bhardwaj :** Will the P.W.D. (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to provide divider on throughout the circular road of Bhiwani ?

Irrigation Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) : Sir, The divider already stands provided in 3.05 km. out of a total length of 5.91 km. As regards the remaining portion, construction of divider will be taken up only after study of traffic movements and right of way.

Dr. Shiv Shankar Bhardwaj : Sir, There is already a lot of congestion on the road in Bhiwani especially on circular road because there is no by-pass. It becomes quite dangerous in the morning hours and in the afternoon when the schools are over. The half of the portion of the road is having divider and half of the road is not having divider. At some places, the road needs to be widened.

There is also a footpath. Somewhere it is 8 feet wide and somewhere it is 18 feet. I would request the Hon'ble Minister that symmetry to the road be provided. It will help in removing the traffic congestion and it will avoid accidents. If the footpaths are also put into order in symmetry, the roads will also get widened.

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, भिवानी के अन्दर 3.05 किलो मीटर के बीच में डिवाईडर प्रोवाईड किया गया है। रोहतक के गेट से देवसर गेट तक ऐसा ऐरिया है जहां पर ज्यादा शॉप्स वगैरा न होने के कारण कन्जैशन नहीं है लेकिन हांसी गेट से घण्टा घर तक दोनों तरफ काफी दुकानें हैं। देवसर पहुँचने के बाद वहां पर काफी कन्जैशन रहती है क्योंकि साईडों मे सभी लोग वहां पर गाड़ियां खड़ी करते हैं जिसकी वजह से वहां पर काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। विशेषतौर पर हांसी चौक से घण्टा घर 800 मीटर का ऐरिया ऐसा है जिसमें काफी ट्रैफिक कन्जैशन है। मैं माननीय सदस्य से एक बात कह सकता हूँ कि जो इनका एरिया है रोहतक गेट से हांसी गेट तक इसमें बस स्टैंड आता है और इसके दोनों तरफ आसपास में काफी दुकानें बनी हुई हैं। इसी प्रकार से घण्टा घर से देवसर गेट तक जो पोरशन है जो कृष्णा चौक से होते हुए आता है यहां पर कई जगह शॉप्स हैं। स्पीकर सर, मैं इनसे इतना ही कह सकता हूँ कि जहां-जहां दोनों तरफ शॉप्स न हों और ईवन चाहे रैजिडैंशियल कॉलोनिज हैं इसको हम एग्जामिन करवाएंगे और जहां प्रोपर लगेगा वहां पर डिवाईडर बनवा देंगे। लेकिन जहां शॉपिंग कॉम्पलैक्स है और यदि वहां पर कन्जैशन है तो वहां पर यह नहीं हो सकेगा। जो बैंक कॉलोनी है उसके आस पास ट्रैफिक की व्यवस्था नहीं है और वहां पर गाड़ियां खड़ी रहती हैं जिसके कारण वहां पर लोगों को बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है।

Dr. Shiv Shankar Bhardwaj : Will the Minister think about constructing a by-pass in Bhiwani to avoid traffic congestion ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जहां तक बाई-पास का सवाल है, उसके लिए माननीय सदस्य मुझे सैपरेट नोटिस दें। अभी पीछे भी एक क्वैश्चन आया था। उस ऐरिया में एक साईड से तो कुछ पोरशन बना हुआ है और कुछ पोरशन ऐसा है जो नहीं बन पाया है। इस पोरशन को हम एग्जामिन करवा लेते हैं। इसमें कन्सलटैंट से जांच करवा लेंगे और उसके बाद उसके ऐस्टिमेटस बनवा लेंगे और यह देख लेते हैं कि वह फिजिबल है या नहीं है। स्पीकर सर, दूसरी बात यह है कि उसको टोल से बनाएं या सरकार के बजट से बनाएं, मैं यह सारा मामला देख कर ही इसके बारे में कोई जवाब दे सकूंगा।

श्री एस०एस० सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि कैथल-पेहवा चौक से करनाल बाई-पास तक बहुत ही चौड़ी सड़क है। यह मुख्य रोड है। उस सड़क के दोनों तरफ सरकारी कोर्टस हैं, रैस्ट हाऊसिज हैं, रैजिडैंशियल ऐरिया और सरकारी दफ्तर भी हैं और वहां पर डी०सी०, एस०पी० के रैजिडैंस भी हैं। वहां पर कोई दुकान नहीं है। क्या मंत्री जी वहां पर डिवाईडर बनवाने का कष्ट करेंगें?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने आपके माध्यम से जो बात सदन में रखी है कि क्या कैथल-पेहवा चौक से करनाल बाई-पास तक डिवाईडर बनाया जाएगा। इसके साथ ही मुझे यह भी बताया गया है कि यह सरकार की तरफ से सैंक्शन है। मैं

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

आपके माध्यम से माननीय साथी जी को यह बताना चाहूँगा कि हम इस बारे में देख लेंगे और अगर वह सरकार की तरफ से मंजूर होगी या मुख्यमंत्री जी द्वारा इस बारे में घोषणा की गई होगी तो सरकार जरूर इस बारे में कार्यवाही करेगी।

श्रीमती अनीता यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूँगी कि यह जो सदन में डिवाईडर्ज बनाने के बारे में बात की जा रही है तो मेरे यहां पर कौसली रेलवे स्टेशन से कनीना तक जो रोड है, यह बहुत ही अच्छा रोड बना हुआ है। उसका डिवाईडर जो बनाया गया था वह नाहड़ गांव में फटता है। एक डिवाईडर कनीना की तरफ चला जाता है। एक डिवाईडर नाहड़, कंवाहड़, बड़ंगी होते हुए बहुझोलरी जाता है। यहां पर रोड बिल्कुल ही खत्म है। क्या मंत्री जी उस रोड को ठीक करवाएंगे? इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कौसली से मातनहेल तक रोड है, के बारे में आश्वासन दिया था, मंत्री जी उसको भी ठीक करवाएं।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने अनाऊंसमैंट की है तो उसको जरूर ठीक करवाएंगे। अध्यक्ष महोदय, जहां तक डिवाईडर की बात की है तो मैं इस बारे में मैडम जी से कहूँगा कि हम इस बारे में चैक करवाएंगे कि वहां पर डिवाईडर बनाने से ज्यादा कन्जैशन न हो जाए इसके बारे में एग्जामिन करवाएंगे। इसके अलावा जो रोड की रिपेयर की बात है, अगर वह टूटी हुई होगी तो हम उसको जरूर रिपेयर करवाएंगे।

श्रीमती अनीता यादव : अध्यक्ष महोदय, डिवाईडर तो आलरेडी बना हुआ है उसको रिपेयर करने की बात है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : मैंने इस बारे में आश्वासन दे दिया है कि अगर वह टूटा हुआ है तो उसको रिपेयर करवा देंगे।

श्री के०एल० शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा है कि 3.05 किलोमीटर पर डिवाईडर बन गया है लेकिन बाकी के डिवाईडर ट्रैफिक की मूवमैंट को देखकर ही बनाए जाएंगे। मेरा तो यह कहना है कि यह सड़क पहले ही ट्रैफिक की मूवमैंट को देखकर ही बनाई जानी चाहिए थी। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि इस जवाब का क्या मतलब है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, रोहतक गेट से देवसर गेट का जो पोरशन है वह वाया दादरी गेट होते हुए आता है, वहां पर रैजिडैंशियल ऐरिया ज्यादा है और शॉपिंग कम्पलैक्स कम हैं। यह उस वक्त बनाया गया था जब वहां पर शॉपिंग कम्पलैक्स वगैरह नहीं थे। जहां की ये मांग कर रहे हैं वहां पर बाजार है और इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि वहां पर घंटा घर से हांसी गेट तक बहुत ही कन्जैशन है। अध्यक्ष महोदय, मैंने जवाब में कहा था कि अगर वहां पर स्पेस अवेलेबल होगा, ट्रैफिक का कन्जैशन नहीं होगा तो हम वहां पर डिवाईडर बनवाएंगे। अब भिवानी में अगर एक गाड़ी खड़ी हो जाए या कोई गाड़ी टेढ़ी कर दे तो वहां से सिर्फ एक गाड़ी ही निकल सकती है।

श्री रणबीर सिंह महेन्द्रा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जवाब में कन्जैशन के बारे में कहा है तो मैं इनको कहना चाहूँगा कि घंटा घर से हांसी चौक तक आलरेडी ही डिवाईडर है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने यही बताया है कि वहां पर डिवाईडर है और उसकी वजह से वहां पर ट्रैफिक की कन्जैशन रहती है। अगर हम उस डिवाईडर को वहां से हटा देंगे तो वहां पर कुछ कन्जैशन कम हो सकती है। मैंने अपने जवाब में यही कहा था।

श्री के०एल० शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जवाब में जो कहा है इसमें यह कहना चाहिए था कि अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस की वजह से बनाएंगे।

कैप्टन अजय सिंह यादव : मैंने अपने जवाब में यही कहा था लेकिन आप सुनते तो नहीं हैं। आप अपनी कमैंटरी शुरू कर देते हैं।

श्री सोमवीर सिंह : स्पीकर साहब, मंत्री जी भीड़ की बात करते हैं। मैं उनको बताना चाहूँगा कि भिवानी में हांसी गेट के ऊपर जो जीपें सवारियाँ ढोती हैं वह बहुत ज्यादा तादाद में वहां पर खड़ी रहती हैं इस कारण वहां पर छोटी-छोटी गाड़ियों को रोड पार करना मुश्किल है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि क्या इसके लिए मंत्री जी कोई जगह निश्चित करवाएंगे, कोई परमानैंट हल निकालेंगे?

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर साहब, मैं तो रोड की बात कर सकता हूँ।

श्री सोमवीर सिंह : मेरा सवाल भी रोड से संबंधित है। मैं भीड़ की ही बात कर रहा हूँ।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, जहां पर इस प्रकार की कमियां पायी जाएंगी वहां पर ऐडमिनिस्ट्रेशन का यही काम है कि वह इस तरह की कमियों को दूर करे। हम कोशिश करेंगे कि वहां पर जीपें न खड़ी हों।

श्री साहिदा खान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या मेवात में भी कोई डिवाईडर बन सकता है?

श्री अध्यक्ष : साहिदा खान जी, आप कौन सी लाईन से मेवात का डिवाईड करना चाहते हो?

श्री साहिदा खान : स्पीकर सर, तावडू से फिरोजपुर झिरका, बलकली, पुन्हाना और सोहना रोड्स पर बहुत जाम रहता है। मंत्री जी को इन सड़कों के बारे में बाखूबी पता है क्योंकि मंत्री जी तो ढाई साल तक वहां की ग्रीवैंसिज कमेटी के चेयरमैन रहे हैं। साथ ही मंत्री जी हमारे पड़ोसी भी हैं इसलिए इनके ऊपर तो हमारा ज्यादा हक बनता है। स्पीकर सर, जो पटौदी रोड नूंह जाती है वहां पर सामने ही अनाज मंडी पड़ती है और वहां पर जो चौक है उसको पटौदी सोहना रोड चौक कहा जाता है। वहां पर दो-दो घंटे जाम लगा रहता है लोग इन जाम की वजह से वहां पर जूझते रहते हैं। इसी तरह से नूंह वाली घाटी के अंदर लोगों को दिक्कत रहती है और इसी प्रकार से फिरोजपुर झिरका के अंदर जाम रहता है। डिप्टी स्पीकर साहब भी यहां बैठे हुए हैं ये इस बारे में बता सकते हैं। स्पीकर सर, जब अलवर साईड में जाना होता है तो वहां पर दो-दो

[श्री साहिदा खान]
घंटे जाम लगता रहता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि कितने दिन में इन रोड्ज पर काम हो जाएगा?

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर साहब, जहां तक मेवात के बारे में सवाल है मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि मेवात एरिया के बारे में मैंने इनको पहले भी बताया था कि अभी फिलहाल ही सरकार ने मेवात के लिए 586 करोड़ रुपये एन०सी०आर० से ऐप्रूव करवाए हैं। हमने होडल, नूंह, पटौदी-पटौदा रोड की वाईडनिंग और स्ट्रैंग्थनिंग ऐप्रूव करवायी है। इसी तरह से हम गुड़गांव, नूंह, पलवल रोड की भी वाईडनिंग और स्ट्रैंग्थनिंग करवाएंगे। जहां-जहां पर बाजार के एरियाज में अगर डिवाईडर प्रदान करने की जरूरत पड़ेगी वहां-वहां पर हम यह काम भी करवाएंगे। हमने एन०सी०आर० से 586 करोड़ रुपये ऐप्रूव करवाए हैं इसलिए हम जल्दी ही काम शुरू करने वाले हैं जिसके बाद वहां की रोड्ज पर कन्जैशन में कमी होगी।

Land Acquired by HUDA for Residential Sectors at Dadri

***939. Major Nirpender Singh Sangwan :** Will the Chief Minister be pleased to State the latest compensation table for land acquired by HUDA for residential sectors in Dadri together with the time by which the plots are likely to be made available for construction of residential buildings ?

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, the rate of compensation for the land under acquisition for Sectors 8 & 9 Part Dadri cannot be informed at this stage since the land has not yet been acquired. Notification under Section 6 of the Land Acquisition Act 1894 was issued for 154.50 acres on 20.2.2008. It is not possible to give the time by which the plots will be available for construction of residential buildings. Possession will be handed over after development works have been completed. अध्यक्ष महोदय, एक बात और मैं इसके साथ माननीय सदस्य की जानकारी के लिए जोड़ना चाहता हूँ कि जहां तक जमीनों का मुआवजा है, क्योंकि अभी जमीन ऐक्वायर नहीं हुई है, इसलिए इसका हम रेट अभी नहीं बता सकते। लेकिन मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए यह बताना चाहूँगा कि एक ऐतिहासिक निर्णय हरियाणा की सरकार ने जमीनों के मुआवजे के बारे में मार्च, 2005 के अंदर लिया था और फिर इसके बाद मुआवजे में और बढ़ोत्तरी की थी। स्पीकर सर, हरियाणा पहला ऐसा प्रान्त है जहां पर फ्लोर रेट की पोलिसी जमीन के अधिग्रहण को लेकर है। इसके मुताबिक ही इस समय जमीन की लोकेशन के मुताबिक 8 लाख रुपये, 16 लाख रुपये और 20 लाख रुपये प्रति एकड़ मुआवजा किसान को मिलता है। फाईनली जब किसान को पेमेंट मिलती है तो तीस प्रतिशत सोलेशियम मिलाकर ब्याज के साथ उसको पेमेंट मिलती है। यह अपने आप में एक अनूठी नीति है। इसके साथ-साथ मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने जो निर्णय किया है वह यह है कि जहां भूमि अधिग्रहण होगी, जो कि पूरे देश में नहीं है और भारत सरकार जो इस बारे में अपनी नीति बना रही है उसके अंदर भी इसे डालने पर विचार कर रही है जिस नीति को हमने लागू किया है। इस

नीति में किसान को 15 हजार रुपये प्रति एकड़ जमीन के कम्पनसेशन के अलावा 33 साल तक मिलेंगे और इसमें हर साल 500 रुपये की बढ़ोत्तरी देने वाला हरियाणा अकेला प्रान्त है। (इस समय मेजें थपथपाई गईं।)

मेजर नृपेन्द्र सिंह सांगवान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि हमारी दादरी वाली जो जमीन है यह 8 लाख रुपये वाले स्लैब में आएगी या 16 लाख और 20 लाख रुपये वाले स्लैब में आएगी?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, यह बात लोकेशन बेस्ड है। जैसा मैंने बताया कि जो चंडीगढ़ के साथ का क्षेत्र है उसका एक रेट है और जो गुड़गांव और एन०सी०आर० का इलाका है उसकी दूसरी स्लैब और बाकी हरियाणा की एक और स्लैब है। 8 लाख रुपये वाली स्लैब में दादरी का एरिया आएगा। इसमें 10 लाख 40 हजार रुपये के करीब सौलेशियम व ब्याज के साथ मिलेगा। सैक्शन 4 की नोटीफिकेशन की डेट से जब तक भूमि की पेमेंट नहीं हो जाती, तब तक 12 प्रतिशत की दर से ब्याज मिलेगा। इसके अलावा 15 हजार रुपये प्रति एकड़ की राशि 33 साल तक और उस राशि पर 500 रुपये की बढ़ोत्तरी हर साल मिलेगी।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि इसमें कोई किसान जो जमीन का मालिक है वह यदि आवश्यक समझे कि मुआवजा उचित नहीं है तो वह कोर्ट में इन्हांसमैंट के लिये भी जा सकते हैं। यदि कोई लोकेशन ऐसी है कि जहां कीमत ज्यादा हैं तो वे इन्हांसमैंट के लिए कोर्ट में जा सकते हैं। यह तो मैंने फ्लोर रेट बताया है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सदन में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के समय मेजर साहब ने जो सवाल उठाया था उसके बारे में मुख्यमंत्री महोदय ने आज ही एक ऐतिहासिक निर्णय किया है कि जो हमारे सिपाही आते हैं, फौजी देश की सेवा करके वापस आते हैं। उन्हें प्लाट आरक्षित करके दिए जाएंगे। माननीय सदस्य ने उनके बारे में जानना चाहा था कि अब तक सारे सैक्टर जनरल कैटेगरी के हैं, क्या कोई सैक्टर डिफैंस सर्विसेज के लिए बनाएंगे, मुख्यमंत्री जी ने उस पर निर्णय ले लिया है और पहला सैक्टर डिफैंस सर्विसेज के लिए ही बनाने जा रहे हैं।

मेजर नृपेन्द्र सिंह सांगवान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि दादरी के अंदर आज की तारीख में कोई प्लॉट अवेलेबल नहीं है। अथोराइज्ड प्लॉट कोई नहीं है। अनअथोराइज्ड प्लॉट लेने पड़ते हैं। आज की तारीख में दादरी सबसे बड़ा सब डिवीजन है। दो हजार के करीब प्लॉट हमें हमारे सिविलियन भाइयों के लिए चाहिएं और तकरीबन एक हजार प्लॉट हमें रिटायर्ड और सर्विंग डिफैंस पर्सोनल के लिए चाहिए। 100 एकड़ भूमि हुडा अधिग्रहित करता है उसमें करीब 550 प्लॉट के करीब उपलब्ध होते हैं। 150 एकड़ कुल भूमि अधिग्रहित की जा रही है। इसमें तकरीबन 750 प्लॉट चाहिएं। हमारी डैफिशिएंसी 2000 प्लॉट्स की है अगर हम जल्द से जल्द बनाएं तो भी हमें एक और सैक्टर बहुत ही जरूरी चाहिए। दादरी में दस सैक्टर जिसको कि डिफैंस सैक्टर के लिए अधिग्रहित करने की योजना थी, उसके

[मेजर नृपेन्द्र सिंह सांगवान]

बारे में मैं चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूँ कि इसको डिफैंस सैक्टर के लिए ही बनाया जाए। 250 एकड़ जमीन से कम में हमारी पूर्ति नहीं होने वाली। आज की तारीख में 3 हजार से 4 हजार अनअथोराइज्ड प्लॉट खरीदने पड़ते हैं।

Mr. Speaker : You should ask the specific question.

मेजर नृपेन्द्र सिंह सांगवान : सर, स्पेसिफिक क्वैश्चन यही है कि इसको जल्द से जल्द बनाया जाए। इसके अतिरिक्त डिफैंस के अलावा एक और सैक्टर बनाया जाए।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है। उसके बारे में मैं यह कहना चाहूँगा कि माननीय सदस्य ने गवर्नर महोदय के अभिभाषण पर बोलते हुए डिफैंस पर्सोनल के लिए प्लॉट काटने की मांग उठाई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी का उदार हृदय है उन्होंने कहा कि दादरी और भिवानी क्षेत्र में फौज के सिपाही ज्यादा हैं जो देश की सेवा में विशेष योगदान देते हैं इसलिए सरकार ने उनके लिए एक अलग से सैक्टर काटने का फैसला किया है। इसके लिए हम माननीय सदस्य से कम से कम धन्यवाद की अपेक्षा जरूर रखते हैं। दूसरा अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने सैक्टर 8 और 9 पार्ट का जिक्र किया है इसके बारे में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि सरकार ने इन सैक्टरों के लिए 154.50 एकड़ जमीन ऐक्वायर कर ली है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह निर्णय लिया है कि हम पहले फौजी सिपाहियों के लिए सैक्टर 8 बनायेंगे और जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए बाद में सैक्टर बनाएंगे। इसके अलावा सरकार ने 151.15 एकड़ भूमि ऐक्वायर करने का फैसला किया है जिसमें सैक्टर 9 और सैक्टर 10 का पार्ट बनाएंगे। पहले 8 और 9 सैक्टर की जो दरख्वास्त आयेंगी उसमें देख लेंगे कितने प्लॉट दिए जायेंगे उसके बाद दूसरा प्रोपोजल सरकार के पास विचाराधीन है क्योंकि सरकार ने जमीन को आईडैंटीफाई कर लिया है। इसलिए पहले सैक्टर के लिए दरख्वास्त का रिस्पौंस देखकर ही दूसरी जमीन लेने के लिए जल्द ही कार्यवाही की जायेगी।

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सरकार ने घोषणा कि है कि जिन किसानों की जमीन एक्वायर हुई है उनको 33 साल तक सरकार 15 हजार रुपये प्रति एकड़ हर साल मुआवजा देगी और हर साल 500 रुपये भी बढ़ायेगी तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूँगी कि जो हुडा ने प्लॉट अलॉट किए हैं क्या 33 साल तक उन अलॉटिज से भी सरकार इन्हांसमैंट का पैसा लेगी?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो प्रश्न पूछा है उसके बारे में मैं उनको बताना चाहूँगा कि जब सरकार उस जमीन का मूल्य आंकेगी तभी उसमें सारा मूल्य शामिल कर लिया जायेगा। यह नहीं कि 33 साल तक अलॉटिज से पैसा लेते रहेंगे। सरकार की मन्शा यह नहीं है। कम्पैन्सेशन निर्धारित करते समय ही यह कीमत तय कर दी जायेगी और अलॉटी को इस एसैसमेंट से ही पैसा देना पड़ेगा। इसलिए यह सही नहीं है कि 33 साल तक अलॉटिज से कोई पैसा इन्हांसमैंट के रूप में लिया जायेगा।

श्रीमती अनिता यादव : अध्यक्ष महोदय, कोसली में 12-15 साल पहले हुडा द्वारा 10-15 एकड़ जमीन में सैक्टर के लिए प्लॉट काटे गये थे। इसमें समस्या यह है कि अनाज मण्डी की जमीन भी हुडा सैक्टर के साथ लगती है। अनाज मण्डी वाले यह कहते हैं कि जब तक हुडा

के सैक्टर वाली जमीन से हमारी जमीन अलग नहीं होगी तो हम बूथ अलॉट नहीं कर सकते और हुडा सैक्टर वाले यह कहते हैं कि जब तक अनाज मण्डी के साथ लगती हमारी जमीन क्लीयर नहीं होती तब तक हम प्लॉट नहीं काट सकते। आम लोगों ने तो 10–15 साल पहले ही अपने पैसे प्लॉट और बूथ के लिए भर दिए थे लेकिन अब तक उनको न तो प्लॉट और बूथ मिले हैं और न ही उनका पैसा मिला है। यह पचरा बहुत दिन से लटका हुआ है। इस बारे में मैं मार्केटिंग कमेटी के ऑफिस में भी गई थी लेकिन आज तक यह मामला सुलझा नहीं है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूँगी कि उन लोगों को कब तक हुडा के प्लॉट मिल जायेंगे और व्यापारियों को ये बूथ कब तक अलॉट हो जायेंगे।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो प्रश्न किया है वह आज ही मुझे इस बारे में लिखकर भिजवा दें। मैं कल दोनों विभागों के अधिकारियों की बैठक बुलाकर इस मामले का निपटारा करवा दूंगा।

श्री नरेश यादव : स्पीकर सर, एन०सी०आर० का दायरा बढ़ाया गया था और उस लिस्ट में अटेली का नाम भी दर्शाया गया था। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या अटेली शहर भी एन०सी०आर० में पड़ता है?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न मूल प्रश्न से अलग है।

आई०जी० शेरसिंह : अध्यक्ष महोदय, हुडा सैक्टर के नाम पर जुलाना में वर्ष 2004 में प्लॉटों के लिए लोगों से दो–दो हजार या तीन–तीन हजार रुपये इकट्ठे किए गये थे और इस प्रकार से एक करोड़ रुपये के लगभग रुपया इकट्ठा किया गया था। क्योंकि मेरे पास इस बारे में रसीदें भी हैं।

श्री अध्यक्ष: आप इस बारे में पहले भी प्रश्न पूछ चुके हैं।

आई०जी० शेरसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास इस बारे में रसीदें हैं और हुडा से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने ऐसा कोई सैक्टर जुलाना में नहीं काटा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या वे इस बारे में जाँच करवायेंगे कि वह पैसा कहां गया?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय आई०जी० साहब ने पहले भी इस बारे में प्रश्न पूछा था और इस बारे में उनको जानकारी दे दी गई थी। 20 रुपये प्रति गज के हिसाब से पैसा लिया गया था, मैंने उस दिन भी इनको इस सदन में सरकार की तरफ से आश्वासन दिया था कि यह सारा पैसा हम अगले 3 महीने के अंदर 5 परसैंट ब्याज के साथ वापिस करेंगे।

डॉ० शिव शंकर भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, भिवानी में भी अनअथोराइण्ड कॉलोनीज की प्रोब्लम है। पिछले 14 मार्च को कुछ शरारती तत्वों ने वहां पर उपद्रव किया, वहां पर एक न्यू डिफैंस कॉलोनी है जहां अधिकतर डिफैंस सर्विसिज से आए हुए लोग रहते हैं और एक बैंक कॉलोनी है वहां 15–20 सालों से मकान बने हुए हैं, वहां सड़कें बनी हुई हैं, बिजली के खम्भे लगे हुए हैं लेकिन टाऊन एण्ड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमैंट की तरफ से उन कॉलोनीज को गिराने के लिए जब पीला पंजा जाता है तो लोग भड़क जाते हैं और काफी उपद्रव हो जाते हैं तो अध्यक्ष

[डॉ० शिव शंकर भारद्वाज]
महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या इन दोनों कॉलोनियों को रेगुलर करने का सरकार का कोई प्रावधान है?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, जहां तक भिवानी का सवाल है तो इस सरकार का बने हुए मकानों को गिराने का कोई इरादा नहीं है, यह केवल लोगों को गुमराह किया जा रहा है। जो नाजायज कब्जा करना चाहते हैं, सरकार उनको ऐसे कब्जे नहीं करने देगी। इसलिए सरकार का साफ फैसला है कि बने हुए मकानों को नहीं गिराया जाएगा।

श्री राधे श्याम शर्मा अमर : मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व की सरकार द्वारा नारनौल के अंदर हुडा के 9 सैक्टर डिवैल्प किए जा रहे हैं यह बहुत अच्छी बात है। नारनौल में भी बहुत अधिक संख्या में देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिक रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या इन सैक्टरों में से एक सैक्टर इन सैनिकों के लिए भी रिजर्व करने का सरकार का कोई विचार है?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी लिखवाकर मुख्यमंत्री महोदय को भिजवा दें क्योंकि इस बारे में मुख्यमंत्री महोदय जी का रवैया हमेशा सकारात्मक है। सरकार सर्वे करवाकर इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी।

श्री रामकुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक बार नारनौंद में हुडा का एक सैक्टर बनाने बारे सवाल किया था तो इन्होंने लिखित में जवाब दिया था कि "नहीं" फिर इन्होंने हाउस में खड़े होकर कहा था कि हमारे यहां एक सैक्टर जरूर बनाएंगे जो कि रिकॉर्ड की बात है तो बाद में जब मैंने इस बारे में पूछा तो ये कहने लगे कि आपके यहां सैक्टर बनाने की हमारी कोई प्रपोजल नहीं है। जहां सी क्लास कमेटियां बनी हुई हैं वहां सरकार की तरफ से इनको खाली करने के लिए बार-बार नोटिस जाते हैं। जहां ये सी क्लास कमेटियां बनी हुई हैं वहां न कोई सीवरेज की सुविधा है और न ही कोई दूसरी सुविधाएं हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि जहां सीवरेज व्यवस्था नहीं है और जहां सैक्टर नहीं बने हुए हैं वहां यह कानून लागू नहीं होना चाहिए क्योंकि लोग कहीं न कहीं तो बसेंगे और कहीं न कहीं तो प्लाट कटेंगे।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा और उनको मालूम भी है कि इन्होंने पिछले सदन में भी एक मांग रखी थी और उससे पिछले सदन में भी इन्होंने एक मांग की थी कि नारनौंद में बस स्टैण्ड बनाया जाए तो मुख्यमंत्री महोदय ने उसकी मंजूरी दे दी है और उसके लिए काफी रुपया भी दे दिया है और पिछले सत्र में इन्होंने मांग की थी कि नारनौंद में सीवरेज व्यवस्था करवाई जाए तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री महोदय ने इसकी भी मंजूरी दे दी है और पैसा भी दे दिया गया है और काम शुरू हो गया है।

श्री रामकिशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, हमारा भिवानी नगरपालिका क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि सरकार का हमारे पिछड़े हुए क्षेत्र के लिए भी कोई हुडा का सैक्टर बनाने का कोई प्रपोजल है?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूँगा कि आज के दिन ऐसा कोई प्रपोजल विचाराधीन नहीं है परन्तु मैं माननीय साथी को कहूँगा कि सफीशियंट नम्बर ऑफ एप्लीकैंट्स अगर तैयार हों तो मुख्यमंत्री महोदय ने साफ कहा हुआ है कि हमारा मन खुला है हम वहां हुडा का सैक्टर काटेंगे इसलिए मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि सफीशियंट नम्बर ऑफ एप्लीकैंट्स का समूह इकट्ठा करके उनकी रिप्रेजैंटेशन मुख्यमंत्री महोदय को दिलवा दें, उसके बाद उस पर विचार कर लिया जाएगा।

श्री एस०एस० सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छी घोषणा की है कि जिनके मकान बने हैं उनके मकान नहीं गिराये जायेंगे। इसके साथ-साथ मैं मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि कैथल शहर में 2-3 हुडा के सैक्टर बने हुए हैं जिनमें कुछ गरीब आदमियों के छोटे-छोटे मकान भी बने हुए हैं, क्या मुख्यमंत्री जी उनको भी रैगूलराईज करने का आश्वासन देंगे?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने on the floor of the House स्पष्ट घोषणा की है कि जिन गरीब, आम और साधारण लोगों ने सैक्टर के अंदर मकान बना रखे हैं और वे मकान हुडा के सैक्टर की प्लानिंग में कोई मेजर रुकावट नहीं डाल रहे होंगे तो उन मकानों को नहीं गिराया जायेगा।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला जी को मालूम है कि कैथल में कितने ज्यादा मकान छोड़े गये हैं, उसके लिए इन्हें सरकार का धन्यवाद करना चाहिए। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि जो मकान बिल्कुल नाजायज बने हुए हैं वह एक विचार करने की बात है। जो मकान सैक्शन-4 से पहले के बने हुए हैं वे मकान नहीं गिराये जायेंगे और जो मकान जमीन अधिग्रहण के बाद बने हैं और इललीगल हैं वे मकान गिराये जायेंगे।

श्रीमती शकुंतला भगवाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूँगी कि बावल में सबसे पहला ग्रोथ सैंटर बना हुआ है लेकिन वहां पर आज तक हुडा का कोई सैक्टर नहीं है। क्या सरकार की बावल में हुडा का कोई सैक्टर बनाने की प्रपोजल विचाराधीन है?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या का पृथक प्रश्न है। इस बारे में माननीय सदस्या लिखित में अलग से जवाब मांग लें, हम लिखित में उनके पास जवाब भिजवा देंगे।

श्री धर्मबीर गाबा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि जो मकान बने हुए हैं वे नहीं गिराये जायेंगे। इस बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि मकान नहीं गिराये जाने का क्या क्राईटेरिया है। बहुत सालों से जो मकान बने हुए हैं क्या उनको नहीं गिराया जाएगा? गुड़गांव के चक्करपुर गांव में 40 साल से लोगों ने मकान बना रखे हैं लेकिन अभी दो दिन पहले वहां पर लोगों को नोटिस मिला है कि उनके मकान गिराये जायेंगे।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मकान गिराये जाने और न गिराये जाने के बारे में बड़े स्पष्ट तौर से, खुले मन से, स्पष्ट नीयत और नीति से

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]
सदन में घोषणा कर दी है। मुझे लगता है कि उसको बार-बार दोहराना उचित नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी ने बड़े स्पष्ट तौर पर बताया है कि जो मकान उस ज़मीन पर धारा-4 लगने से पहले के बने हुए हैं वे मकान अगर सैक्टर की प्लानिंग के अंदर मेजर आब्सट्रैक्सन नहीं करते, जिनमें थोड़ी बहुत गुंजाइश है और इधर-उधर से सड़क निकल सकती है तो वे मकान नहीं गिराये जायेंगे। यह सरकार का वायदा है। किसी एक जगह के बारे में हम floor of the House आश्वासन नहीं दे सकते। माननीय साथी ने जिस गांव का जिक्र किया है उसके बारे में ये मुख्यमंत्री जी को लिखकर भिजवा दें उसको एग्जामिन करवाकर हम कोई पोजीटिव हल निकाल लेंगे।

श्री धर्मबीर गाबा : अध्यक्ष महोदय, जिन मकानों को बने हुए 40 साल हो गये उनको भी तोड़ने के लिए नीचे के लैवल पर नोटिस दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है तो उनको नोटिस क्यों दिए जा रहे हैं?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को बताना चाहूँगा कि इस नीति का यह मतलब नहीं है कि प्रान्त के अंदर अन रैगुलेटिड डिवैल्पमैंट शुरू हो जाये। जो नीति सरकार ने बनाई है उसका मतलब यह है कि यदि किसी आम, साधारण और गरीब आदमी ने किसी समय में अन-प्लांड एरिया में मकान बना लिया है और उसे बने हुए वर्षों बीत गये हैं। इस प्रकार के बने हुये मकानों को सरकार नहीं गिरायेगी। मैं मेरे माननीय साथी को एक बात और बताना चाहूँगा कि यह सही बात है कि जनता के हक में फैसला लेना सरकार का फर्ज होता है। हमारे मुख्यमंत्री पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने उदार हृदय से इस प्रकार की उदार नीति लोगों के हित को ध्यान में रखकर लागू की है। पिछली सरकार के समय में गुड़गांव के अलावा दूसरे शहरों में भी सिलैक्टिव तरीके से लोगों के मकान डिमोलिश किए जाते थे। इस प्रकार का काम जो लोग सरकार के पक्षधर थे वे करवाते थे। इस तरह की मंशा उस समय की सरकार के पक्षधर लोगों की थी और गुड़गांव के अन्दर भी जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी बताया है कि पिछली सरकार द्वारा बहुत सारे नोटिसिज़ जारी करके गुड़गांव और दूसरे शहरों के अन्दर बहुत सारी ऐसी कॉलोनीज़ को रैगूलराईज़ किया गया है। जैसा मैंने पहले भी बताया है It would have to be decided on a case to case basis. Our intention is not to demolish anybody's house, our intention is, if somebody has constructed a house, we must try and adjust it within our planning. Unless and until it comes within sector roads or some such facilities where it is impossible then we will have to take that away, otherwise we will do so, Sir. सैक्शन-4 लागू होने से पहले की कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। आपके जो स्पैसिफिक सुझाव हैं जैसा कि मैंने पहले भी बताया है आप माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखकर भिजवा दें, हम उस केस की जानकारी पता करके पूरे तथ्यों के अनुसार पॉजीटिव तरीके से आपको सूचित करेंगे।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल दादरी से शुरू होकर पूरे हरियाणा में फैल गया है। इससे यह जाहिर होता है कि यह समस्या सारे हरियाणा की है। मुख्यमंत्री महोदय और मंत्री जी ने इसके समाधान के लिए जवाब भी दिये हैं जो कि काबिले तारीफ हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, यह समस्या सारे हरियाणा की इसलिए है कि हम बढ़ती हुई आबादी और दूसरी जरूरतों के मुताबिक पहले ही से वहां पर सैक्टर्ज के लिए व्यवस्था नहीं करते। अगर हम पहले से ही ऐसा करते तो आज जो इतनी अनवांटिड कॉलोनीज़ की ग्रोथ हो

रही है तकरीबन उन शहरों में खास तौर से बड़े कस्बों में और फरीदाबाद भी उसका एक हिस्सा है तो मैं एक बात आपके माध्यम से कहना भी चाहूँगा और बताना भी चाहूँगा कि 70-80 परसैंट तक ये अनअथॉराइज्ड कॉलोनीज़ बन गई हैं। ये अनअथॉराइज्ड कॉलोनियां इसलिए बनी क्योंकि वहां पर सरकारी स्तर पर कोई अथॉराइज्ड सैक्टर नहीं बन पाया और अथॉराइज्ड सैक्टर न बनने की वजह से अनअथॉराइज्ड कॉलोनीज़ डिवैल्प हो गई। जहां 70-80 परसैंट चाहे वह सारे हरियाणा में कहीं भी हो ये डिवैल्पमैंट हो गई हैं एक तो उनको अथॉराइज्ड किया जाये और दूसरे सैक्टर बनाकर उस शहर की सूरत न बिगाड़ें इसके लिए सरकार कोई कारगर कदम उठाये। इसके अलावा सारे हरियाणा में एक सर्वे करवाया जाये कि जहां-जहां जिन कस्बों में, कमेटीज़ में और बड़े शहरों में जहां आवश्यकता है उसके मुताबिक हम पहले ही या तो जमीन एक्वायर करें और या फिर प्राईवेट सैक्टर को उसके लिए इजाजत दें जिससे कि यह अनवांटिड ग्रोथ रुक सके और इस समस्या का स्थाई समाधान हो सके।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिंता जाहिर की है वह वाजिब है। इससे सम्बन्धित पूरे आंकड़े तो मेरे पास नहीं हैं क्योंकि यह मसला इस सवाल से जुड़ा हुआ नहीं था। फिर भी मैं आपके माध्यम से सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार आने से पहले जब कोड ऑफ कंडक्ट लगना था तो उससे पहले बड़ी हड़बड़ी में एक ऑर्डर के तहत बहुत से सैक्टर्ज और कॉलोनियों को रैगुलराईज़ किया गया। परन्तु जब मौजूदा सरकार ने कार्यभार सम्भाला अध्यक्ष महोदय, उसके बाद सैंकड़ों की संख्या में वह कॉलोनीज़ हैं जो कि अन-अथोराईज्ड थी। जो बन गई थी और जिनके अन्दर कोई सुविधा नहीं थी। परन्तु फिर सरकार ने उन सबको रैगूलराईज़ करने का निर्णय लिया। हमने पानी, सीवरेज और सड़कें इस प्रकार की तमाम सुविधायें वहां पर उपलब्ध करवाई। अध्यक्ष महोदय, जहां तक हुडा का प्रश्न है तो हुडा अब तक 26 अलग-अलग शहरों में 190 सैक्टर्ज डिवैल्प कर चुका है और इसके तहत 2 लाख 49 हजार 98 प्लाट्स काटे जा चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ आज के दिन जहां पर हुडा अर्बन एस्टेट बनाने जा रहा है उनमें नारायणगढ़, शाहबाद, गोहाना, हांसी, पटौदी, अग्रोहा, सफीदों, तरावड़ी, पेहवा और महेन्द्रगढ़ शामिल हैं। इन सभी शहरों के अन्दर हम हुडा की अर्बन एस्टेट बना रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां भी यह जरूरी लगेगा, जैसा कि मैंने बताया, आखिर में हुडा द्वारा वहां पर ही सैक्टर्ज डिवैल्प किये जायेंगे, जहां पर सफीशिएंट मांग होगी। माननीय सदस्य को और भी जहां पर यह नज़र आता है कि वहां पर हुडा सैक्टर डिवैल्प करे तो ये हमें बतायें वहां मांग के मुताबिक हुडा द्वारा सैक्टर्ज डिवैल्प किये जायेंगे। हुडा इस जिम्मेवारी से पीछे नहीं हटेगा। जहां तक प्राईवेट लाइसैंसिज़ की बात है, प्राईवेट कॉलोनाईजर्स की बात है, तो सरकार ने इस बारे में भी जो छोटे कस्बे और शहर हैं वहां पर उदार ह्रदय से यह नीति बनाई है कि अगर आपके पास 25 एकड़ जमीन है और अगर आप सारी सुविधाएं प्रोवाईड करेंगे और उनको शहरों की सुविधाओं से लिंकेजिज देंगे तो वह भी हम परमिट करते हैं। जैसे-जैसे दरख्वास्त आती हैं उनको मैरिट के आधार पर कंसीडर किया जाता है।

Status of Municipal Committee to Nangal Chaudhary

***933. Sh. Naresh Yadav :** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to State whether there is any proposal under consideration of the

[Sh. Naresh Yadav]

Government to give the status of Municipal Committee to Nangal Chaudhary ?

Urban Development Minister (Shri A.C. Chaudhary) : No, Sir.

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, नांगल चौधरी जो कि नई कंस्टीच्यूंसी बनी है। राजस्थान जाने वाले हाई-वे से जुड़े होने के कारण अटेली तथा नांगल चौधरी में आबादी लगभग बराबर है। सबसे बड़ी बात यह है कि नांगल चौधरी में चारों तरफ से क्रैशर, रोड़ी और पत्थर लेने के लिए पूरे हरियाणा से लोग आते हैं। यहां पर सड़कें भी टूटी पड़ी हैं और बस अड्डा भी नहीं है। यहां पर म्यूनिसिपल कमेटी बनाने की भी बहुत जरूरत है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि इसको म्यूनिसिपल कमेटी बना दिया जाये तो हमारा उद्धार हो सकता है।

श्री ए०सी० चौधरी : अध्यक्ष महोदय, किसी भी कस्बे को म्यूनिसिपैल्टी में कंवर्ट करने के लिए कुछ पॉलिसी तय की गई हैं और उस लिहाज से हमारे पास सिर्फ एक बार एक रिप्रेजैन्टेशन आई थी जिसको अपने तौर तरीके से हमने जिला कलैक्टर से जानकारी हासिल करनी चाही उसके बारे में कोई पॉजिटिव रिपोर्ट अभी तक हमारे पास नहीं आई। अगर कोई ऐसी रिक्वायरमैंट कभी आई तो सरकार कभी भी ना नहीं करेगी। लेकिन सच यह है कि जो बड़े कस्बे म्यूनिसिपैल्टीज में कंवर्ट हो करके नये नाम एक्वायर करना चाहते हैं वे न तो घर के रहते हैं और न ही घाट के। जो विकास के बारे विभाग की गाँवों के उत्थान की स्कीम हैं उनका भी फायदा नहीं उठा पायेंगे और दूसरी तरफ उनके पास साधन भी नहीं हैं। जैसे साथी नरेश यादव जी कह रहे हैं, बस अड्डा भी नहीं है, सड़कें भी नहीं हैं। उनके पास बजट भी नहीं है। उनके पास रैवेन्यू के सोर्सिज भी नहीं हैं। तो वह न केवल सरकार के लिए बल्कि माननीय प्रतिनिधि के लिए भी सिरदर्दी बन जायेगी। मैं चाहूँगा कि इस मामले में वे जरूरत के आधार पर कोई बात कहेंगे तो उस पर विचार कर लिया जायेगा।

श्री धर्मबीर गाबा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि मंत्री जी ने कहा कि उसे रैवेन्यू मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या सरकार अमैंडमैंट 74 के तहत बाऊंड नहीं है कि एक पर्टीकुलर आबादी के लिए एक म्यूनिसिपल कमेटी जरूर बनाई जाए। दूसरे जो म्यूनिसिपल कमेटी आपने रिवाईज की हैं उसके बावजूद वहां पर 20-20 हजार की आबादी वाले इलाके आपने छोड़ दिये हैं। उदाहरण के तौर पर हसनपुर और पुन्हाना को आप छोड़ रहे हैं। आखिर किस बिनाह पर छोड़ा गया है कोई तो क्राईटेरिया होगा? वैसे क्राईटेरिया नहीं भी है तो भी सरकार संविधान संशोधन 74 के तहत म्यूनिसिपल कमेटी बनाने के लिए बाऊंड है उनको तो आपको बनाना ही चाहिए।

श्री ए०सी० चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक बात स्पष्ट शब्दों में कही है कि किसी शहर को म्यूनिसिपल कमेटी का दर्जा देने के लिए क्राईटेरिया फिक्स है। 50 हजार से नीचे वाले शहरों में म्यूनिसिपल कमेटी होगी, 50 हजार से 3 लाख के बीच की आबादी के लिए म्यूनिसिपल कांउसिल होगी और 3 लाख से ऊपर म्यूनिसिपल कार्पोरेशन होगी जो कि एक पहले से ही फरीदाबाद में है और दूसरी अब गुड़गांव में बनने जा रही है। जहाँ तक सरकार का बाऊंड होने का ताल्लुक है, मैं नहीं समझ पाया कि माननीय श्री गाबा साहब किस कानून का हवाला दे रहे हैं जो हमें बाऊंड करता है। दूसरे अगर म्यूनिसिपल कमेटी बना भी दी जाये तो इस बात का तो हमें खास तौर पर ध्यान रखना होगा कि हमें कितनी चुंगी-चौंकियाँ बनानी होंगी, कितने स्टाफ की भर्ती करनी

होगी। कमेटी का ऑफिस किस प्रकार से लांच करना होगा और कम से कम स्टाफ को तनख्वाह देने के लिए तो पैसा कमेटी से निकाला जाये। महज लॉयबलिटी लेकर अपने तौर पर कहीं पर म्यूनिसिपल कमेटी बनाने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री उदय भान : अध्यक्ष महोदय, हसनपुर कस्बे में बहुत पुरानी नगरपालिका थी जो पिछली सरकार ने द्वेषपूर्ण नीति के कारण भंग कर दी थी। उसके बाद जो दूसरी नगरपालिकाएं भंग की गई थीं उनमें से 8-9 नगरपालिकाएं तो बहाल कर दी गई थीं लेकिन हसनपुर की नगरपालिका बहाल नहीं की गई थी। वहां पर अनाज मण्डी है, ब्लॉक भी है, पुलिस स्टेशन भी है, वहां पर कॉलेज भी है। इस तरह से हसनपुर नगरपालिका बनाए जाने के सारे नॉर्म्ज पूरे करता है और उसके लिए सरकार को कोई भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से सरकार ने अन्य 8-9 नगरपालिकाओं को बहाल किया है क्या हसनपुर की नगरपालिका को भी बहाल करेंगे? अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैंने एक प्रश्न भी दिया हुआ था लेकिन वह प्रश्न लगा नहीं। क्या मन्त्री जी उदारता दिखाते हुये हसनपुर नगरपालिका को बहाल करने की कृपा करेंगे?

श्री ए०सी० चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि पिछली सरकार ने हसनपुर म्यूनिसिपल कमेटी को खत्म कर दिया। अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने उसे खत्म किया है गुनाह तो उन्होंने किया है। मैं यह जरूर चाहूँगा कि इनकी नगरपालिका को बहाल करने पर विचार किया जाये। स्पीकर सर, जैसा मैंने कहा है कि हमारी सरकार शहर और देहात दोनों का ही सर्वांगीण विकास चाहती है। यदि किसी तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव आता है तो हम उस पर जरूर विचार करेंगे। मैं इसकी फाईल निकलवा कर देख लूंगा कि क्या मैरिट पर उस कमेटी को खत्म किया गया है और क्या ऐसे कोई कारण बने हैं जिनके कारण हम इसे रिवाईव कर सकते हैं तो हर हालत में उसको रिवाईव करेंगे।

Constitution of Administrative Reforms Commission

***837. Sh. Shamsher Singh Surjewala :** Will the Chief Minister be pleased to state :—

(a) whether the Government of Haryana has constituted an Administrative Reforms Commission in the State;

(b) if so, the terms and reference of the Commission;

(c) whether any Administrative Reforms Commission was constituted previously; and

(d) if so, what is the report of previous Commission ?

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) :

(क) हां, श्रीमान् जी।

(ख) श्रीमान जी, आयोग के संदर्भ की शर्तें निम्नलिखित हैं :—

1. सरकार द्वारा सेवाओं की पूर्ण रूप से सुपुर्दगी में दक्षता, आर्थिक, पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्वों को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार में संगठनात्मक

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

संरचना तथा विभागों के संचालन के ढंगों में उचित बदलाव की सिफारिश करना।

2. वातावरण सृजन करने के तरीकों की सिफारिश करना जहां सरकारी कृत्यकारी लोगों के प्रति सौजन्यता, समझदारी तथा पूर्ण सहायता के लिए उत्तरदायी हो।

3. सरकारी कृत्यकारिओं के व्यवहार में अधिक पारदर्शिता एवं ईमानदारी को लाने के लिए शासन चलाने में सदाचार को उन्नत करने के तरीकों की सिफारिश करना।

4. मोनीटरिंग तथा मूल्यांकन प्रणाली से सम्बन्धित विकेन्द्रीकरण कार्मिक तथा कार्यक्रम दोनों उपायों की सिफारिश करना।

5. प्रशासकीय मामलों के तीव्र प्रस्तावों के प्रति अच्छे तालमेल के लिए शक्तियों के अधिक विकेन्द्रीकरण हेतु उचित पहलुओं पर सिफारिश करना।

6. सभी विभागों में तथा स्तरों पर ई-गर्वनैंस को अधिक बढ़ावा देने के लिए सुझाव देना।

(ग) नहीं, श्रीमान जी।

(घ) श्रीमान जी, प्रश्न नहीं उठता।

श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, ऐसा ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिफोर्म कमीशन बनाने के लिए मैंने 2005 के बजट सैशन में बोलते हुये कहा था और सरकार ने तीन साल के बाद इस आयोग का गठन किया है, देर आयद दुरुस्त आयद। स्पीकर सर, क्या उसकी रिपोर्ट पर अमल इसी सरकार के टैन्योर में लागू हो सकेगा?

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, यह तो हाईपोथैटिकल सवाल है और यह रिपोर्ट आने के बाद की बात है। (विघ्न) पहले रिपोर्ट आएगी तो सरकार उसको लागू भी करवाएगी। दलाल साहब, बहुत ही सीनियर और वाईड एक्सपीरियंस के व्यक्ति हैं।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी ने यह बात यहां पर उठाई थी कि हरियाणा में ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिफोर्म कमीशन की बहुत आवश्यकता है। कोई भी माननीय सदस्य जब कोई सुझाव देता है तो माननीय मुख्यमन्त्री जी खुद उस को गम्भीरता से लेते हैं और उस पर बाकायदा मन्त्रणा होती है। मन्त्रणा करके माननीय मुख्यमन्त्री जी को लगा कि इस कमीशन के गठन की जरूरत है। ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिफोर्म कमीशन की इन्टैरिम रिपोर्ट अभी तक सरकार को प्राप्त नहीं हुई है फिर भी मैं माननीय सदस्य जी को बताना चाहूँगा कि कर्ण सिंह दलाल जी उनके पड़ौस में बैठते हैं और वे इस कमीशन के चेयरपर्सन भी हैं, वे बहुत सूझ-बूझ रखने वाले व्यक्ति हैं और हम उम्मीद करते है कि वे इस ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिफोर्म कमीशन की रिपोर्ट में बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव सरकार को देंगे।

Recruitment to the post of Joint Director, Animal Husbandry Department

***914 Sh. Karan Singh Dalal :** Will the Animal Husbandry & Dairying Minister be pleased to state :—

(a) whether any direct recruitment to the post of Joint Director (Animal Husbandry) was made by the Government on the recommendation of HPSC during the year 2003;

(b) if so the name of the person and the date of requisition sent by the Administrative Department together with the date of advertisement and the date of recommendation letter of HPSC;

(c) whether there was any provision of direct recruitment of the post as specified in (a) above in the Haryana Veterinary (Group-A) Service Rules 1995;

(d) whether the recruitment to post as mentioned in (a) above was contrary to the provisions of Haryana Veterinary (Group-A) Service Rules 1995; and

(e) if so the action taken by the Government or proposed to be taken by the Government in this regard ?

Agriculture Minister (Sardar H.S. Chatha) :

(a) Yes, Sir.

(b) Sir, Dr. Virender Singh was appointed as Joint Director (Animal Husbandry) on the recommendation of H.P.S.C. during 2003. The requisition was sent to H.P.S.C. on 5.6.2003 by the Government. The said post was advertised on 16.6.2003 and the recommendation was made by the H.P.S.C. on 22.8.2003.

(c) Yes Sir, as per amendment dated 9.5.2003 in Haryana Veterinary (Group-A) Service Rules, 1995, there was provision for the direct recruitment.

(d) No Sir.

(e) Question does not arise.

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से मेरी यह सप्लीमैंटरी है कि क्या मंत्री जी यह जानते हैं कि डॉ० विरेन्द्र सिंह पिछली सरकार के समय के मुख्यमंत्री जी के दामाद हैं और ये इस विभाग में डिप्टी डायरैक्टर लगे हुये थे? इनकी प्रमोशन ज्वायंट डायरैक्टर के पद पर नहीं हो सकती थी। इस विभाग ने 2003 में तमाम रूल्ज को बड़ी ही जल्दबाजी में बदला और इस पोस्ट को बाई प्रमोशन भरा जाना उचित समझा। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि ऐसी क्या जरूरत विभाग में आन पड़ी थी कि एक व्यक्ति जो उन दिनों के मुख्यमंत्री के दामाद थे उनके लिए यह पोस्ट क्रिएट की गई और जल्दबाजी में रूल्ज अमैंड किए गए? अध्यक्ष महोदय, जिस महोदय को इस पोस्ट पर अप्वायंट किया गया था आज वे श्रीमान कहां पर पोस्टिड हैं और क्या काम कर रहे हैं?

सरदार एच०एस० चट्ठा : अध्यक्ष महोदय, यह तो मुझे नहीं पता है कि दामाद है कि नहीं हैं लेकिन मुझे यह सुनने में जरूर आया था कि यह आदमी पुराने चीफ मिनिस्टर के दामाद हैं। इसके अलावा माननीय सदस्य की यह बात दुरुस्त है कि बड़ी हरीली यह ऐड की गई थी। 5 तारीख को अमैंडमैंट की गई थी और अगली 5 तारीख को पब्लिक सर्विस कमिशन को लिखा गया था। 16.6.2003 को पब्लिक सर्विस कमिशन ने विज्ञापित किया था। 26 तारीख को अप्वायंट कर दिया और 27 तारीख को ज्वायनिंग भी करवा दी। लेकिन इस बारे में मेरी प्रार्थना है कि यह सिलैक्शन पब्लिक सर्विस कमिशन ने की है और वह ऐडवरटाईजमैंट के थ्रू की है। हां, यह बात ठीक है कि यह अप्वायंटमैंट बहुत जल्दी में की गई है। जहां तक इनका सवाल है कि वह आजकल कहां पर है, तो मैं इनको बताना चाहूँगा कि उसने स्टडी के लिए छुट्टी ली हुई हैं। पहले छुट्टी 188 दिन की थी, फिर 336 दिन की छुट्टी ली और फिर दोबारा से 187 दिन की छुट्टी ली हैं। यह टोटल 711 दिन की छुट्टी बनती है जोकि अभी पूरी नहीं हुई है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या विभाग ने इस बारे में कभी जानने की कोशिश की है कि यह व्यक्ति वाकई में पढ़ाई-लिखाई के लिए छुट्टी पर है या तोशाम की खानों आदि की देखभाल कर रहा है?

सरदार एच०एस० चट्ठा : अध्यक्ष महोदय, उसने डिपार्टमैंट को छुट्टी के लिए अप्लाई किया और डिपार्टमैंट ने उसको छुट्टी दी है। लेकिन विभाग 120 दिन से ज्यादा दिन की छुट्टी नहीं दे सकता है। जब उसने ज्यादा छुट्टी के लिए अप्लाई किया था तो उसका केस फाईनांस डिपार्टमैंट को भेजा गया था और अब फाईनांस डिपार्टमैंट ने उसे छुट्टी देने के लिए अलाऊ कर दिया है। अब मुझे नहीं पता है कि वह विदेश में 'कान' में कुछ स्टडी कर रहा है या खानों में कुछ कर रहा है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, कर्ण सिंह जी यह जानना चाहते हैं कि Is there any documentary proof that he has really gone on study leave ?

सरदार एच०एस० चट्ठा : अध्यक्ष महोदय, वह परमिशन लेकर स्टडी के लिए गया है। वह स्टडी कर रहा है या नहीं कर रहा है इस बात का मुझे ज्ञान नहीं है लेकिन हम इस बात की जांच करवा लेंगे।

15.00 बजे

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, जब इनकी नियुक्ति कर दी गयी तो इसके बाद इनको अप्वायंटमैंट लैटर दिया गया। इस अप्वायंटमैंट लैटर की तीसरी शर्त में यह जिक्र है कि the particulars of these examination/test/training etc. which the candidate was required to go through during the period of probation. इसलिए इसकी तो इंफोर्मेशन डिपार्टमैंट के पास होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्री जी बताएंगे कि इनकी नियुक्ति की शर्तों के मुताबिक प्रोबेशन पीरियड में इनकी कौन-कौन सी परीक्षाएं ली गयीं, कौन-कौन से इनके टैस्ट लिए गए और उन परीक्षाओं और टैस्ट्स की क्या-क्या स्थिति रहीं? मंत्री जी ने जो यह कहा कि वे नहीं जानते तो क्या मंत्री जी सदन को आश्वास्त करेंगे कि इनकी जांच करवायी जाएगी कि जो ये छुट्टी लेकर पढ़ाई करने गए हैं और पढ़ाई ये नहीं कर रहे हैं तथा अगर यह सच्चाई है तो क्या उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी?

सरदार एच०एस० चड्ढा : स्पीकर सर, बहुत बढ़िया बात मेरे लर्नेड भाई ने की है, हम पूरी जांच करवाएंगे। अगर वे पढ़ाई करने के लिए छुट्टी लेकर गए हैं और यदि वे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो we will proceed against him.

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, आपने दलाल साहब के दूसरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या उनके टैस्ट लिए गए या नहीं और अगर लिए गए तो उनकी क्या स्थिति रही?

सरदार एच०एस० चड्ढा : स्पीकर सर, जहां तक इनके दूसरे सवाल की बात है, अगर किसी आदमी के एक साल या दो साल के प्रोबेशन पीरियड में उसके खिलाफ कोई बात नहीं है और यदि वह ठीक काम कर रहा है तथा यदि आपके पास पोस्ट है तो हमें उसको रैगुलर तो करना पड़ेगा।

श्री कर्ण सिंह दलाल : सर, यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ क्योंकि पिछली सरकार ने अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को गलत तरीके से फायदा पहुँचाया।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आपके सवाल का जवाब आ गया है मंत्री जी ने कहा है कि उनके खिलाफ जांच करवाएंगे कि वह पढ़ाई कर रहा है या नहीं accordingly they will take the action. इसलिए अब आप बैठें।

Illegal Mining

***887 Sh. Bhupinder Chaudhary :** Will the Mines and Geology Minister be pleased to state whether it is a fact that illegal mining in the villages like Gairatpur Bas, Manesar, Sikohpur, Naurangpur etc. is still going on despite the orders of the Hon'ble Supreme Court banning the activity of mining in Gurgaon District; if so, the steps taken by the Government to check the illegal mining in Gurgaon District ?

Industries Minister (Shri Lachhman Dass Arora) : No, Sir.

श्री भूपेन्द्र चौधरी : स्पीकर सर, सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कहा था कि गुड़गांव जिले में अवैध माईनिंग नहीं होगी। जब फारेस्ट कंट्रोलर वहां पर एक दिन गए तो वहां पर माईनिंग चल रही थी। स्पीकर सर, यह माईनिंग वहां पर लगातार चल रही है जबकि डिपार्टमैंट यह कहता रहा है कि वहां पर माईनिंग नहीं चल रही है। सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहां पर रैगुलर माईनिंग हो रही है। जो वहां पर अवैध माईनिंग की जा रही है उनको संबंधित ऑफिसर से नोटिस भी इशु हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या वे इस अवैध माईनिंग को रुकवाएंगे?

श्री लक्ष्मण दास अरोड़ा : स्पीकर सर, जहां तक मेरे आदरणीय साथी का प्रश्न है, मैं इनको बताना चाहूँगा कि वहां पर कोई माईनिंग नहीं चल रही है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, माननीय सदस्य तो कह रहे हैं कि वहां माईनिंग चल रही है। क्या आप वहां पर अपने विभाग की कोई टीम भेजकर इस बारे में जांच करवाएंगे?

श्री लक्ष्मण दास अरोड़ा : स्पीकर साहब, हमने इस बारे में सारा सर्वे करवाया है। छोटे मोटे 14 केसिज में ही इस बारे में एफ०आई०आर० लौज हुई है और इनके खिलाफ भी कार्यवाही हो रही है।

Setting-up of SEZ by Reliance Industries Limited

***810 Dr. Sita Ram** : Will the Industries Minister be pleased to state:—

(a) whether the Government is aware of the fact that the Reliance Industries Limited is likely to set-up a Special Economic Zone in the State ;

(b) if so, the name of place and the total acreage of land (Agricultural and Non-Agricultural) acquired by the Government for the setting up of above said SEZ and the date on which possession of the said land was given togetherwith the details thereof ; and

(c) the rate at which compensation was being paid to the owners of the land and the rate at which the above said land was being given to the Reliance Industries Limited ?

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) :

(a) Yes, Sir.

(b) State Government acquired land for setting up of Special Economic Zone by Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Limited. (HSIIDC) measuring 1484 Acre 4 Kanal 19 Marla in the revenue estate of villages Khandsa, Narsinghpur, Mohammedpur Jharsa, Garoli Khurd and Harsaru in tehsil & district, Gurgaon, out of which land measuring 1383.68 acre was transferred to Reliance Haryana SEZ Limited, a joint venture company of HSIIDC and Reliance Venture Limited (100% owned subsidiary of Reliance Industries Limited) for the setting up of Special Economic Zone. The possession of the land was given on 6.12.2006. The details of the land are as under :

1.	Village Khandsa	— 129.52 acre
2.	Village Mohammedpur Jharsa	— 298.62 acre
3.	Village Narsinghpur	— 42.26 acre
4.	Village Garoli Khurd	— 242.59 acre
5.	Village Harsaru	— 670.69 acre

(c) The compensation was paid to the owners of the land at the

average rate of Rs. 21.17 lacs per acre. The land was transferred to Reliance Haryana Special Economic Zone Limited at the rate of Rs. 27.52 lacs per acre.

श्री अध्यक्ष : ऑनरेबल मैम्बर्ज, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है।

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Foreign tour by the Chief Minister

***888. Dr. Sushil Indora :** Will the Chief Minister be pleased to state :—

(a) the tour undertaken by the Chief Minister to foreign Countries after taking over as Chief Minister in the State in March, 2005, together with the details, of countries visited.

(b) the total amount incurred on the said tours and the names of the Officers/MLA's accompanied, together with the detail of achievement made therefrom, and

(c) the details of agreement / MOU signed ?

उद्योग मंत्री (श्री लक्ष्मण दास अरोड़ा) :

एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

[श्री लक्ष्मण दास अरोड़ा]

विवरण

(क एवं ख) मुख्यमंत्री द्वारा किए गए दौरे, वहन किए गए खर्च, साथ गए अधिकारियों/विधायकों के नाम तथा उपलब्धियाँ निम्न प्रकार से हैं :—

क्रम संख्या	वर्ष	देशों के स्थानों के नाम	प्रतिनिधियों का विवरण	की गई यात्रा की तिथि	खर्च की गई धनराशि (रुपयों में)	उपलब्धियाँ
1	2	3	4	5	6	7
1.	2005-06	जापान तथा कोरिया, गण-राज्य	सर्वश्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, मुख्यमंत्री हरियाणा, लक्ष्मण दास अरोड़ा, उद्योग मंत्री हरियाणा, एम०एल० तायल, आई.ए.एस., प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री, पी०के० चौधरी, आई.ए.एस., वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, उद्योग, अशोक लवासा, आई.ए.एस., रेजीडेन्ट आयुक्त, राजीव अरोड़ा, आई.ए.एस., प्रबन्ध निदेशक, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं संरचना विकास निगम, डी०आर० धींगड़ा, आई.ए.एस., निदेशक, उद्योग, एम०एस० चोपड़ा, विशेष कार्यकारी अधिकारी-II/ मुख्यमंत्री, सुरजीत सिंह, सीटीपी/हरियाणा	26.11.2005 से 4.12.05 तक	26,10,074	दौरों से 2200 करोड़ रुपये का निवेश मिला। सैमसंग, याकूल्ट, वाइकेके, मितसुई किंजौक, कम्पोनैन्टस, अशाही ग्लास, युकालफयूल सिस्टमज, इंडिया जापान लाइटिंग, केहिन फाई, एनटीएन मैन्युफैक्चरिंग, फाइन कैमिकल्ज, पोस्को स्टील, कायकोडीयर एब्रेसिब, डायमंड इलैक्ट्रिकल तथा पारकर इंजिनियरिंग जैसी जापानी एवं कोरियन कम्पनियों ने 837.19 करोड़ रुपये के निवेश के साथ हरियाणा में अपनी परियोजनाएं क्रियान्वित कर दी है। मारुति उद्योग लिमिटेड ने 4895 करोड़ रुपये का पूंजी

			राज्य औद्योगिक संरचना विकास निगम, राकेश टुटेजा, उपमहाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य औद्योगिक संरचना विकास निगम।			निवेश करके हाल ही में आईएमटी मानेसर में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है। इस कम्पनी का 10,000 करोड़ रुपये निवेश करने की योजना है, जिसमें इसके वैण्डर्ज द्वारा 5000 करोड़ रुपये शामिल है।
2.	2006-07	नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, यू०के० तथा स्पेन	सर्वश्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, मुख्यमंत्री हरियाणा, लक्ष्मण दास अरोड़ा, उद्योग मंत्री हरियाणा, कै० अजय सिंह यादव राजस्व मंत्री, एम० एल० तायल, आई.ए.एस., प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री, पी०के० चौधरी, आई.ए.एस., वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, उद्योग, अशोक लवासा, आई.ए.एस., रेजीडेन्ट आयुक्त, राजीव अरोड़ा, आई.ए.एस., प्रबन्ध निदेशक, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं संरचना विकास निगम, डी०आर० धींगड़ा आई.ए.एस., निदेशक, उद्योग, एम०एस० चोपड़ा, विशेष कार्यकारी अधिकारी-II/ मुख्यमंत्री, शादी लाल कपूर, वरिष्ठ सचिव/मुख्यमंत्री, राकेश टुटेजा, उप-महाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य औद्योगिक	8.10.2006 से 19.10.06 तक	82,14,598	दौरों से 10 वर्षों के दौरान 12000 करोड़ रुपये का विनिवेश मिलेगा। अभिरुची का एक वक्तव्य हस्ताक्षरित हुआ, जो हरियाणा में एक यूरोपियन टैक्नोलॉजी पार्क की स्थापना के लिए डच हरियाणा बिजनैस कन्सोर्टियम के साथ हस्ताक्षर किए गए। ओसराम (सिमन्ज एजी की एक सहायक कम्पनी) जे०सी०बी० तथा अलस्टोम ने भी राज्य में परियोजनाओं को स्थापित करने में दिलचस्पी दिखाई फोलोअप के रूप में कुण्डली में मैसर्ज ओसराम को 10 एकड़ प्लॉट अलॉट किया गया है तथा मैसर्ज जे० सी०बी० को भी उनके विस्तार परि-योजना के लिए 10 एकड़ प्लॉट सैक्टर

[श्री लक्ष्मण दास अरोड़ा]

1	2	3	4	5	6	7
			संरचना विकास निगम, मनोज पाल सिंह, सहायक महाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य औद्योगिक संरचना विकास निगम।			58, फरीदाबाद में, गांव मांगर में 500 एकड़ पर एक यूरोपियन टैक्नोलॉजी पार्क विकसित किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें डच हरियाणा बिजनैस कन्सोर्टियम तथा हरियाणा औद्योगिक एवं संरचना विकास निगम द्वारा संयुक्त रूप से एस.पी.वी. के तहत शामिल होना है। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं संरचना विकास निगम को इस परि-योजना में शेयर होल्डिंग की 10 प्रतिशत के बराबर स्वीट इक्विटी मिलेगी।
3.	2006-07	चीन तथा सींगापुर	सर्वश्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, मुख्यमंत्री हरियाणा, फूल चंद मुलाना, शिक्षा मंत्री, लक्ष्मण दास अरोड़ा, उद्योग मंत्री, हरियाणा, धर्मवीर सिंह, मुख्य संसदीय सचिव, शादी लाल बत्रा, विधायक, अध्यक्ष हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, एम०एल० तायल, आई.ए.एस., प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री, पी०के० चौधरी, आई.ए.एस., वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव,	26.11.2006 से 4.12.06 तक	26,04,431	यह दौरा इन्टरनैशनल डिपार्टमैंट ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, चीन तथा बाहरी मामलें मंत्रालय, भारत सरकार के मध्य आदान-प्रदान कार्यक्रम का एक हिस्सा था। अभिरुचि के क्षेत्र, विशेष आर्थिक जोन (सेज) तथा चीन में संरचना विकास का अध्ययन करना था।

			उद्योग, राजीव अरोड़ा, आई.ए.एस., प्रबन्ध निदेशक, हरियाणा राज्य औद्योगिक संरचना विकास निगम, डी०आर० धींगड़ा, आई.ए.एस., निदेशक, उद्योग, एम०एस० चोपड़ा, विशेष कार्यकारी अधिकारी-II/ मुख्यमंत्री, शादी लाल कपूर, वरिष्ठ सचिव/ मुख्यमंत्री, राकेश टुटेजा, उपमहाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं संरचना विकास निगम, मनोज पाल सिंह, सहायक महाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य औद्योगिक संरचना विकास निगम।			
4.	2007-08	यू०एस०ए०, कनाडा एवं जर्मनी	सर्वश्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, मुख्यमंत्री हरियाणा, फूल चंद मुलाना, अध्यक्ष बीस सूत्री कार्यक्रम, कैप्टन अजय सिंह यादव, सिंचाई मंत्री, शादी लाल बत्रा, विधायक, अध्यक्ष हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, एम०एल० तायल, आई.ए.एस., प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री, पी०के० चौधरी, आई.ए.एस., वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, उद्योग, राजीव अरोड़ा, आई.ए.एस., प्रबन्ध निदेशक, हरियाणा राज्य औद्योगिक संरचना विकास	8.10.2007 से 20.10.07 तक	1,04,73,555	इन दौरों से 3750 करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त हुआ। खाद्य संरक्षण तथा प्रोसैसिंग उद्योग में स्पैकट्रम इन्टरनैशनल एल०एल०सी०/मैसर्ज होलीस्टर इन्क (यू०एस०ए०) जो चिकित्सा देखभाल (ओस्टोमी) उत्पादों का एक विख्यात निर्माता है, का 100% का इओयू स्थापित करने का प्रस्ताव है। रिको ऑटो इन्डस्ट्रिज लिमिटेड तथा मैग्ना पावर ट्रैन के मध्य ऑटो मोबाइल में समान संयुक्त उद्यम के लिए एक समझौते पर

[श्री लक्ष्मण दास अरोड़ा]

1	2	3	4	5	6	7
			निगम, डी०आर० धींगड़ा, आई.ए.एस., निदेशक, उद्योग, एम०एस० चोपड़ा, विशेष कार्यकारी अधिकारी-II/ मुख्यमंत्री, शादी लाल कपूर, वरिष्ठ सचिव/मुख्यमंत्री, सलील नारंग, उप-महाप्रबंधक, हरियाणा राज्य औद्योगिक संरचना विकास निगम, राकेश टुटेजा, उपमहाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य औद्योगिक संरचना विकास निगम।			हस्ताक्षर किए गए थे। डॉ० फ्रेश जो औरल हाइजीन में एक विख्यात ब्राण्ड के अध्यक्ष हैं। उन्होंने गुड़गांव में आईटी/ आईटीईएस सेज की स्थापना के लिए घोषणा की मोन्टगोमरी कॉलेज तथा हरियाणा राज्य के एक एम०ओ०यू० पर हस्ताक्षर किए गए थे। जिसके अनुसार मोन्टगोमेरी कॉलेज, हरियाणा के विश्व-विद्यालय के साथ व्यवसाय पाठ्यक्रम भागीदारी नीति योजना, विद्यार्थी अदला-बदली तथा विचार-विमर्श के प्रावधान के माध्यम से राज्य को कॉलेज के उत्तम व्यवसायों को अपनाने में सहायता करेगा। हरियाणा राज्य में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की स्थापना के लिए दो प्रस्ताव भी प्राप्त हुए।
					2,39,02,658	

नोट :— यू०एस०ए०, कनाडा एवं जर्मनी से संबंधित विदेशी दौरे जो 8 से 20 अक्तूबर, 2007 तक किए गए हैं, उनका खर्च अस्थाई है तथा खर्च/लेखा एवं ऑडिट को अन्तिम रूप देने की शर्त पर है।

हस्ताक्षर किए गए समझौते / एम०ओ०यू० का विवरण निम्न प्रकार से है :—

1. अभिरूचि का एक विवरण (एस०ओ०आई०) 12000 करोड़ रुपये (10 वर्षों की अवधि में 2 बिलियन यूरो) के निवेश से हरियाणा में एक यूरोपियन टैक्नोलॉजी पार्क स्थापित करने के लिए हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं संरचना विकास निगम तथा डच हरियाणा बिजनैस कन्सोंटियम के मध्य हस्ताक्षरित किया गया था।

2. मोन्टगोमरी कॉलेज तथा हरियाणा राज्य के मध्य एक एम०ओ०यू० पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके अनुसार मोन्टगोमरी कॉलेज का हरियाणा के विश्वविद्यालयों के साथ व्यवसाय, विकास, पाठ्यक्रम भागीदारी नीति योजना विद्यार्थी अदला-बदली में सहायता करेगा।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Qualification of Members of H.P.S.C.

***113. Sh. Karan Singh Dalal :** Will the Chief Minister be pleased to state the qualifications and categories of Official/Non-official Members and Chairmen of the Haryana Public Service Commission since 1996 till date alongwith the dates of their appointment and retirement/resignation.

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) :

श्रीमान् जी, सूची सदन के पटल पर रखी जाती है।

विवरण

हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों/सदस्यों की दिनांक 1.1.1996 से अब तक की सूची।

क्र० सं०	अध्यक्षों/सदस्यों के नाम	योग्यताएं	श्रेणी सरकारी/ गैर-सरकारी	नियुक्ति की तिथि	सेवा निवृत्ति/ त्यागपत्र की तिथि
1.	श्री गोबिन्द ठुकराल, सदस्य	एम.ए. (अंग्रेजी)	गैर-सरकारी	26.5.1996	14.3.2002/ त्यागपत्र 3.7.1997
2.	श्री एन.एन. यादव, सदस्य	एम.एस.सी. (भौतिकी)	सरकारी	18.9.1996	3.5.2002
3.	श्री एम.एस. राठी, सदस्य	बी.ए.	सरकारी	26.5.1996	14.5.1998
4.	श्री नरेन्द्र सिंह, सदस्य	बी.ए., एल.एल.बी.	गैर-सरकारी	17.6.1998	16.6.2004
5.	श्री दयाल सिंह, सदस्य	बी.एस.सी. (इंजिनियरिंग)	सरकारी	3.7.1998	2.7.2004
6.	श्री जगदीश राय, सदस्य	एम.ए., बी.ए. (ऑनर्स)	सरकारी	18.7.1998	17.7.2004
7.	श्री एल.डी. मैहता, अध्यक्ष	बी.ए., एल.एल.बी.	गैर-सरकारी	22.9.1999	31.7.2000
8.	श्री एम.एस. शास्त्री, सदस्य	बी.ए.एल.एल.बी. शास्त्री (ओ.टी.)	सरकारी	28.2.2000	27.2.2006 त्यागपत्र 6.12.2004
9.	श्री एम.एस. सैनी, सदस्य	बी.ए.एम.एस.	गैर-सरकारी	7.7.2000	6.7.2006 त्यागपत्र 1.12.2004

क्र० सं०	अध्यक्षों/सदस्यों के नाम	योग्यताएं	श्रेणी सरकारी/ गैर-सरकारी	नियुक्ति की तिथि	सेवा निवृत्ति/ त्यागपत्र की तिथि
10.	श्री के.सी. बांगड़, अध्यक्ष	पी.एच.डी.(यू.के.) आर.आई.टी.ई. और ए.वी.एच. फैलो	गैर-सरकारी	2.8.2000	1.8.2006 त्यागपत्र 1.12.2004
11.	श्री गुलशन भारद्वाज, सदस्य	बी.ए.,एल.एल.बी.	गैर-सरकारी	4.4.2001	9.8.2004
12.	श्री एस.के. गुप्ता, सदस्य	बी.ए.	गैर-सरकारी	4.4.2001	3.4.2007 त्यागपत्र 5.7.2004
13.	श्री प्रदीप चौधरी, सदस्य	बी.ए.	गैर-सरकारी	10.5.2002	9.5.2008 त्यागपत्र 5.7.2004
14.	श्री डूंगर राम, सदस्य	एम.ए. (अंग्रेजी)	सरकारी	5.7.2004	9.6.2009
15.	श्री छतर सिंह, सदस्य	बी.ई. (बिजली)	सरकारी	5.7.2004	4.7.2010
16.	श्री युद्धवीर सिंह, सदस्य	बी.ए.	गैर-सरकारी	5.7.2004	4.7.2010
17.	श्री सतबीर सिंह, सदस्य	बी.ए. (ऑनर्स) एल.एल.बी.	गैर-सरकारी	5.7.2004	4.4.2010
18.	श्री ओम प्रकाश, सदस्य	बी.ए.,एल.एल.बी.	सरकारी	10.8.2004	9.8.2010
19.	डॉ० रनबीर सिंह हुड्डा, सदस्य	एम.एस.सी. (एग्रोनोमी), पी.एच.डी., एल.एल.बी.	गैर-सरकारी	10.8.2004	9.8.2010
20.	श्री मेहर सिंह सैनी, अध्यक्ष	बी.ए.एम.एस.	गैर-सरकारी	1.12.2004	30.11.2010
21.	श्रीमती संतोष सिंह, सदस्य	एम.एस.सी., बी.एड.	गैर-सरकारी	1.12.2004	30.11.2010
22.	श्री राम कुमार कश्यप, सदस्य	एम.ए.(अर्थशास्त्र), एल.एल.बी.	सरकारी	15.12.2004	14.12.2010

सदन की मेज पर रखे गए कागज-पत्र

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will lay papers on the Table of the House.

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to lay on the Table —

The Annual Statement of Accounts of Housing Board, Haryana for the year 2005-06, as required under section 19-A(3) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.

The 7th Annual Report of Dakshin Haryana Bijli Vitran Nigam Limited for the year 2005-2006, as required under section 619-A(3)(b) of the Companies Act, 1956.

The 8th Annual Report of Haryana Vidyut Prasaran Nigam Limited for the year 2004-2005, as required under section 619-A(3)(b) of the Companies Act, 1956.

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भ)

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान (पाई) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए जो समय दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं और अभिभाषण पर बात करने से पहले अपने साथियों की ही तर्ज पर मैं भी आपका बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आपने अच्छा भवन और अच्छी सराउंडिंग्स हमें दी हैं। इसके लिए आपको और पी०डब्ल्यू०डी० विभाग के सभी उच्च अधिकारियों से लेकर सभी को बहुत बधाई देता हूँ। स्पीकर सर, जिस प्रकार से वार्षिक योजना का आकार विगत तीन वर्षों में लगभग तीन गुना बढ़ा है इसके लिए मुख्यमंत्री जी और सरकार बधाई के पात्र हैं। हर तरफ काफी तरक्की के काम हो रहे हैं जो कि बहुत ही सराहनीय हैं। सबसे ज्यादा लैंडमार्क काम सरकार ने किसानों की जमीनों के रेट देकर किया है। मेरे हल्के में पिछले राज में 1.5 लाख रुपये पर एकड़ के हिसाब से जमीन अधिग्रहण के मामले में किसान को उसकी जमीन का मुआवजा दिया जाता था। आज यह स्थिति है कि जब किसी प्रोजैक्ट के लिए या विकास के कार्य के लिए जमीन का अधिग्रहण सरकार द्वारा किया जाता है तो किसान निराश नहीं होता है। यह बहुत बड़ा लैंडमार्क निर्णय सरकार ने लिया है जिसके तहत किसान को 33 साल तक 15 हजार रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष और 30 हजार रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष भिन्न-भिन्न स्कीमों में दिये जाते हैं और उसमें क्रमशः 500 रुपये और एक हजार रुपये प्रति वर्ष की दर से बढ़ौत्तरी भी की जाती है। हमने भी इतने वर्षों तक किसान की राजनीति की है लेकिन ऐसी योजना पहले कभी नहीं देखी। इसी वजह से दिल्ली में केन्द्र के फाइनैंस मिनिस्टर साहब ने अपनी बजट स्पीच में मुख्यमंत्री जी का विशेष तौर पर जिक्र किया। सारे देश में हरियाणा की तर्ज पर इस फैसले को कॉपी करने की कोशिश की जा रही है। ऐग्रीकल्चर

पर आते हुए मैं यह भी कहना चाहूँगा कि नैचुरल कैलेमिटी पर भी सरकार ने किसान की बहुत ज्यादा मदद की है। इस लाइन पर मेरा यह सुझाव है कि जब ओलावृष्टि होती है या कोई अन्य नुकसान होता है तो उस वक्त किसान की सारी आशा उसकी फसल पर लगी हुई होती है। आमतौर पर किसान को गेहूँ और जीरी में 20-25 हजार रुपये का पैकेज मिलता है। मेरा निवेदन है कि सरकार के पास क्योंकि इस समय रिसोर्सिज बहुत ही अच्छे हैं इसलिए मेरा सुझाव है कि इस मुआवजा राशि को बढ़ाना चाहिए। आज के संदर्भ में कुछ कीमतें बढ़ा दी हैं और कुछ कीमतें किसानों की जिंसों की भी बढ़ी हैं लेकिन फिर भी पर-एकड़ मुआवजे का रेट 50 परसैंट जरूर बढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है। इंश्योरैंस की सरकार ने बढ़िया नीति लागू की है लेकिन मेरा अनुभव है और मैं समझता हूँ कि इंश्योरैंस का जो लाभ किसान को होना चाहिए वह नहीं हो रहा है। इफ एंड बट्स बहुत ज्यादा हैं। इंश्योरैंस कंपनीज किसान को बहुत ज्यादा ऐक्सप्लौयट करती हैं। सरकार से भी प्रीमियम की राशि ले लेती हैं और व्यक्तिगत तौर पर भी कहीं मौका लगता है तो प्रीमियम राशि लेने से नहीं चूकती हैं लेकिन जब देने का समय आता है तो तरह-तरह की अड़चनें अड़ाने की चेष्टा की जाती है। सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। जब कभी भी ओलावृष्टि होती है तो पूरे गांव में किसान को उसका नुकसान नहीं होता है। जब कभी फ्लड आता है तब भी पूरे गांव में नुकसान नहीं होता है। यदि किसान का किसी किनारे पर नुकसान हो जाता है तो वह इस इंश्योरैंस के लाभ से वंचित रहेगा। इस बारे में सरकार को ध्यान देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, आपने गन्नौर में नयी मंडी बनाने की पेशकश की है। काफी अर्सा पहले यह मंडी कुंडली में बनाने की बात कही गई थी। पिछली सरकार ने वेस्टेड इंट्रस्ट की वजह से जमीन और जगह इस्तेमाल की और इंडस्ट्रीज के लिए प्लाट्स देकर मकसद हासिल किया। स्पीकर सर, हमारी सरकार ने कोआप्रेटिव लोन के ऊपर लगभग 800 करोड़ रुपये की राशि को माफ करने का प्रावधान किया है। इससे जनता जनार्धन के सामने और लोनिज के बैनीफिसरीज के सामने यह सवाल रखा कि आप अपना असल पैसा अदा कर दीजिए आपका जितना भी ब्याज है वह माफ हो जायेगा। बीच-बीच में भी कर्जा माफी के नाम का इस बारे में कभी ब्यान आ गया कभी किसी का ब्यान आ गया और लोग इस लोन का सिर्फ 400-450 करोड़ रुपये के लगभग फायदा उठा पाये जैसा कि माननीय वित्त मंत्री जी श्री बीरेन्द्र सिंह जी ने कहा। लेकिन एक बड़ी विडम्बना दिल्ली की केन्द्र सरकार ने की कि उसने 60 हजार करोड़ रुपये का किसानों का कर्जा माफ करने की घोषणा की। देश भर के अन्दर इस बात की बहुत चर्चा है और किसान बहुत खुश हैं। लेकिन एक और चर्चा किसानों की रूप रेखा की अभी सामने नहीं आई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारा दायित्व बनता है खासकर माननीय मुख्यमंत्री जी का जिन्होंने किसानों को साधन-सम्पन्न बनाने का एक बीड़ा उठाया है। हालांकि पार्लियामेंट में अभी इस बारे में डिसकशन होना बाकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि इस लोन माफी के जो पैसे का वितरण है एम०पीज० के माध्यम से इस तरह से करवायें यह क्लीयर करवाया जाए कि जो विलफुल डिफाल्टर्ज हैं और दूसरे वाकई गरीबी के कारण डिफाल्टर्ज हैं। जो विलफुल डिफाल्टर्ज हैं उन लोगों के किसी न किसी तरह से सरकार को पर कतरने चाहिएं वरना वे आगे भी इसी तरह से डिफाल्टर्ज होते रहेंगे। जैसा हमने अपना कर्जा अदा कर दिया लेकिन हम बीच में फंस गये। न तो हमें इसका फायदा मिला न हम डिफाल्टर्ज हैं। इस प्रकार की सिच्यूएशन को भी कवर करना चाहिए कि 60 हजार करोड़ रुपये के पैकेज के अन्दर यह होना चाहिए कि जो वाकई लोन लेकर देना चाहते हैं उनको भी इसके अन्दर पूरा लाभ मिलना चाहिए ताकि उससे हमारा लैन-देन का सिस्टम है और जो

[श्री तेजेन्द्रपाल सिंह मान]

हमारा लेन-देन का बैंकिंग सिस्टम है उसका एतबार बना रहना चाहिए। क्योंकि हम भी कोआप्रेटिव सैक्टर से काफी सालों से जुड़े हुए हैं। इसलिए सरकार को ऐसा कुछ करना चाहिए कि जो 60 हजार करोड़ रुपये का कर्जा माफ किया है उसको किसी न किसी प्रकार से जो वाकई में अपना लेना-देना जानते हैं उनको इस से लाभ हो सके। वरना बैंक फेल हो जायेंगे। आज ऐसा माहौल बन जायेगा कि आई बार इस तरह के डिफाल्टर्ज ही फायदा उठायेंगे। यह गलत प्रथा तो हमारे साथ बैठे विपक्ष के साथियों ने शुरू की थी। अगर इस तरह से डिफाल्टर्ज को ही फायदा होता रहा तो आगे से कोई भी लोन वापिस नहीं करेगा। स्पीकर सर, मैं बहुत अर्से से कोआप्रेटिव सैक्टर से जुड़ा हुआ हूँ। स्पीकर सर, कोआप्रेटिव सोसायटी के अन्दर 50 सालों की जद्दोजहद के बाद हम गांवों में खाद, पानी, कर्जा सारी चीजें पहुँचा पाये हैं। कोआप्रेटिव डिपार्टमैंट ने हर गांव के अन्दर सोसायटी का दफ्तर बना दिया था। मुझे कम से कम इस बात का खेद है कि उसमें 7-8 गांवों की सोसायटी को मिलाकर जो पैक बनाई है तो एक जगह जहां बैंक ट्रावल करते थे वहां हम ट्रावल करेंगे जिसके कारण इस पर बहुत सारा फण्ड वेस्ट होगा क्योंकि किसान अपनी हर जरूरत के लिए एक गांव से दूसरे गांव जायेगा और शायद जो हम इकोनोमिक की सुविधा देना चाहते हैं उसकी बजाए गरीब आदमी पर ज्यादा बोझ पड़ेगा। इस प्रकार की बात पी०ए०सी० की मीटिंग में भी आई थी और इस सवाल पर कोआप्रेटिव डिपार्टमैंट के अधिकारियों ने भी माना था कि इससे काफी दिक्कत की शिकायतें सामने आई हैं और जो फायदा होना चाहिए वह नहीं हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह आग्रह करूंगा कि उन्हें इस बारे में स्टडी करवानी चाहिए ताकि जो फायदा आप करने जा रहे हैं ऐसा न हो कि किसान के फायदे की बजाए नुकसान ज्यादा हो जाये। स्पीकर सर, हमारे यहां खेती के तरीके बदल रहे हैं जो खेती के इम्प्लीमैंटस के ऊपर भारत सरकार ने सब्सिडी दी है। मुझे बहुत खुशी है कि रोटावेटर नया इम्प्लीमैंट आया है जिसके ऊपर पंजाब में इम्प्लीमैंट मनुफैक्चरर ने एक ड्रील लगा दी है जिसके बाद यह इम्पलीमैंट एक ही ऑप्रेशन में गेहूँ की बिजाई कर देता है। मैं यह सुझाव देना चाहूँगा कि सरकार इन इम्प्लीमैंटस पर डायरेक्ट सब्सिडी किसानों को दें। ऐसा न हो कि सरकार मनुफैक्चरर को सब्सिडी दे तो वे किसान को एक्सप्लॉयट करें। इस तरह से डीजल बचेगा और इससे साधन बचेंगे और पर्यावरण भी ठीक होगा। इसलिए इस रोटावेटर इम्पलीमैंट पर सब्सिडी बढ़ानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मान साहब, आप कन्कलूड कीजिए आपको बोलते हुए दस मिनट हो गये हैं।

श्री तेजेन्द्रपाल सिंह मान : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ सुझाव देना चाहूँगा जो बेशकीमती सुझाव हैं और जब आप कहेंगे तभी बैठ जाऊंगा। अध्यक्ष महोदय, वैटरनरी यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। मुर्रा ब्रीड के लिए मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कई जिले सिलैक्ट किए गए हैं उनमें मेरा जिला कैथल भी है। मुर्रा भैंसों की बहुत भारी कीमत हो गई है, एक-एक भैंस 30-30 हजार रुपये से लेकर एक-एक लाख रुपये तक की बिकती है और जैसा कि अभी एक सवाल के जवाब में बताया गया है कि हर गांव के अंदर वैटरनरी का एक रिप्रेंजटेटिव होगा तो मेरा सुझाव है कि हर गांव में वैटरनरी के रिप्रेजैंटेटिव की बजाय एक वैटरनरी डिस्पैंसरी बनाई जाए ताकि गरीब आदमी जिनके जानवर एमरजैंसी में मर जाते हैं उनके जानवर बच सकें और उनका नुकसान न हो। जिन लोगों का पशु पालन का काम है और वे दूध की पैदावार करते हैं तो मेरा सुझाव है कि दूध का कोई न कोई मिनीमम स्पोर्ट प्राइज होना चाहिए क्योंकि मिल्क

प्रड्यूसर्स का बहुत एक्सप्लॉएटेशन हो रहा है। मिल्क प्लांट को आदेश होना चाहिए कि हर गांव में मिल्क कोलैक्शन सैंटर होगा। दूधिए गांव से 8 रुपये किलो, कभी 10 रुपये किलो और कभी 11 रुपये किलो के हिसाब से दूध लेते हैं लेकिन जब कभी दूध ज्यादा हो जाता है तो दूधिए रेट कम कर देते हैं और वे गरीब किसानों का पैसा लौटाते नहीं हैं। पिछले 3 सालों में मुख्यमंत्री ने वेवर्स की लाइन लगा दी हैं। मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री महोदय ने हर गरीब व्यक्ति को, हर क्लास को और हर वर्ग को कुछ न कुछ दिया है जिसके लिए सरकार बधाई की पात्र है।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं फोरैस्ट के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। फोरैस्ट में मेरा कुछ अनुभव भी है, पिछली सरकार में 'हरियाली' नाम की एक योजना थी, बड़े खेद की बात है कि उस योजना का एक-एक रुपया उस समय के स्थानीय एम०एल०एज० ने अधिकारियों के साथ मिलकर खाया है और एक भी पेड़ नहीं लगाया। यह ऐसा विभाग है जिसमें पेड़ लगाने में खर्चा ज्यादा आता है और उसको मेन्टेन करने में खर्चा कम आता है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूँगा कि जहां कहीं पेड़ लगे हुए हैं वहां देखा जाए कि वे बड़े हो रहे हैं या नहीं और उनकी पूरी तरह देखभाल होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, इरीगेशन में बहुत तरक्की हो रही है इसके लिए मैं इरीगेशन मिनिस्टर और मुख्यमंत्री महोदय का आभारी हूँ। इरीगेशन के मामले में मेरे क्षेत्र में भी बहुत से काम हुए हैं लेकिन मेरा सुझाव है कि जो नालों की अब रिपेयर हो रही है मैंने पहले भी मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह किया था कि इसमें 9 इंच की दीवारें बननी चाहिएं, 4 इंच की दीवार बनाने से वह ज्यादा देर चलती नहीं है और इससे नैशनल रेवेन्यू वेस्ट हो रहा है इसलिए मैं चाहूँगा कि इन खालों की दीवारें 9 इंच की बनानी चाहिएं इससे स्टेट का फायदा होगा और लोगों का भी फायदा होगा।

श्री अध्यक्ष : मान साहब, आप वाइंड-अप करें।

श्री तेजेन्द्रपाल सिंह मान : अध्यक्ष महोदय, पब्लिक हैल्थ में भी बहुत पैसा लगा है लेकिन इसमें क्वांटिटी और क्वालिटी की मोनीटरिंग की बहुत जरूरत है। इंदिरा गांधी पेयजल योजना के नाम से जो योजना चालू की गई है इस बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि एक-एक घर में कई-कई राशन कार्ड हैं और वे 5-5 टंकियां ले लेते हैं, एक टंकी लगा लेते हैं और 4 टंकियां बेच देते हैं इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इस मामले में निरीक्षण होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, आज हम सब जानते हैं कि बिजली की कमी है और बिजली की कमी को दूर करने की पूरी कोशिश हो रही है। मेरे हल्के में 3 सब-स्टेशन बन रहे हैं और 2 सब-स्टेशन अपग्रेड हुए हैं और 3 और सब-स्टेशन बनने की सम्भावना है इसके लिए मैं मुख्यमंत्री महोदय और सरकार का आभारी हूँ।

अध्यक्ष महोदय, सड़कों के क्षेत्र में भी बहुत काम हुए हैं, मेरे हल्के में भी जब मुख्यमंत्री महोदय आए थे तो कई सड़कों की मंजूरी देकर आए थे, मुझे खुशी है कि उन सबके ऊपर टैण्डर्ज हो गए हैं और उन पर काम होगा। अध्यक्ष महोदय, मोटे तौर पर सारे हरियाणा के रोड्स का इन्फ्रास्ट्रक्चर बन गया है। अध्यक्ष महोदय, हमारे इलाके में गेहूँ और जीरी का उत्पादन ज्यादा है लेकिन हमारे यहां जमीन की सोयल इतनी चिकनी है कि जीरी निकालने में दिक्कत होती है इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जहां पर भी कृषि की उत्पादन क्षमता ज्यादा है और जितने भी कंसोलिडेटिड

[श्री तेजेन्द्रपाल सिंह मान]

पाथस हैं जहां-जहां से मार्किटिंग कमेटी को कृषि से आमदन ज्यादा है उन इलाकों में कंडीशन ऐसी है कि बरसात के मौसम में पानी रास्तों में इकट्ठा हो जाता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि वहां सड़कें पक्के तरीके से बनाई जाएं। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के बारे में मैं जिक्र जरूर करना चाहूँगा वैसे मुझे कहना तो बहुत कुछ था लेकिन आप मुझे वाइंड-अप करने के लिए कह रहे हैं। इसलिए शिक्षा के मामले में मैं कुछ कहना चाहूँगा और मुझे बहुत खेद है कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत दादरी के पास हम पी०ए०सी० के साथ डाइट की बिल्डिंग देखने के लिए गए। वहां सारे कमरे भरे हुए थे। हमने वहां पूछा कि कमरे भरे हुए क्यों हैं तो उन्होंने जवाब दिया हमें पता नहीं, सामान आया था और हमने रख दिया। हमने इस बारे में सारी रिपोर्ट भेज दी है। हमने कैथल में भी विजिट किया था वहां 31 मार्च को सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से 30 मार्च को पैसा आया और 31 मार्च तक सारा पैसा खुर्द-बुर्द हो गया।

श्री अध्यक्ष : मान साहब, प्लीज अब आप बैठें। आप अपनी बात लिखवा कर भिजवा देना।

श्री तेजेन्द्रपाल सिंह मान : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहकर वाइंड-अप करता हूँ। मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहूँगा कि जो पी०एच०सीज० दूर दराज के एरियाज में हैं वहां पर डॉक्टर्ज नहीं जाते हैं। सरकार की तरफ से पी०एच०सीज० के लिए करोड़ों रुपये लगाकर बड़ी-बड़ी बिल्डिंग बनाई जाती हैं लेकिन डॉक्टर्ज के अभाव में लोगों को हैल्थ सुविधा नहीं मिल पाती। मेरे हल्के में भी तीन पी०एच०सीज० की बिल्डिंग्ज बनाई जायेंगी इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे जो डॉक्टर्ज हैं उनको सैलरी का अच्छा पैकेज दिया जाये ताकि वे सरकारी नौकरी करें। चाहे पी०जी०आई० के डॉक्टर हों या दूसरे डॉक्टर हों। आज के दिन डॉक्टर सरकारी नौकरी छोड़कर प्राईवेट नौकरी कर रहे हैं क्योंकि उनको प्राईवेट में ज्यादा सैलरी मिलती है। इसलिए सरकार इस ओर विशेष ध्यान दे। इसके साथ-साथ मैं यह भी अर्ज करना चाहूँगा कि जहां तक रूरल हैल्थ की बात है जब भी सरकार की तरफ से डॉक्टर्ज की नियुक्ति की जायें तो जिस समय एडवर्टाइजमैंट की जाये उस समय पी०एच०सीज० की लिस्ट बना दी जाये कि जो-जो डॉक्टर सिलैक्ट होंगे उनको फलां-फलां दस पी०एच०सीज० में से किसी एक में काम करना पड़ेगा तभी जाकर हम रूरल हैल्थ की तरफ ध्यान दे पायेंगे वरना पी०एच०सीज० में कोई भी डॉक्टर नौकरी करने के लिए तैयार नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, मैंने सिविल वैलफेयर के बारे में भी कुछ बातें कहनी थी लेकिन समय कम होने की वजह से मैं अपनी बातों को यहीं विराम देता हूँ और आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा जी, आपकी पार्टी के मैंबर्ज में से 43 मिनट एक मैम्बर बोल चुके हैं, उसके बाद 77 मिनट एक और मैम्बर बोल चुके हैं और उसके अलावा आपकी पार्टी के दो मैंबर्ज रामफल चिड़ाना जी और ईश्वर सिंह पलाका जी को भी 33 मिनट का समय दिया गया। प्लीज आप बैठें, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अब तक 36 मैंबर बोल चुके हैं। आप बजट पर बोल लेना। (विघ्न)

श्री उदयभान (हसनपुर, अनुसूचित जाति) : अध्यक्ष महोदय, 7 मार्च को राज्यपाल महोदय ने सदन में जो अभिभाषण दिया है मैं उसके अनुमोदन में और समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा सरकार का और केन्द्र सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि केन्द्र सरकार ने 60 हजार करोड़ रुपये के किसानों के कर्जे माफ करके बहुत ही अभूतपूर्व कदम उठाया है। केन्द्र सरकार ने न सिर्फ किसानों के कर्जे माफ किए हैं बल्कि एक टाईम बाउंड समय भी निर्धारित किया है कि 30 जून तक सभी के कर्जे माफ कर दिये जायेंगे और भविष्य में कर्ज पर ब्याज दर भी 7 प्रतिशत की गई है उसकी जितनी सराहना की जाये वह कम है। **(इस समय सभापतियों की सूची में से माननीय सदस्य श्री आनंद सिंह दांगी पदासीन हुए।)** सभापति महोदय, मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी को बधाई देता हूँ कि इस तरह के क्रांतिकारी कदमों की शुरुआत उन्होंने सबसे पहले हरियाणा प्रदेश से शुरू की जिसका अनुसरण हमारी केन्द्र सरकार ने भी किया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने सत्ता सम्भालते ही किसानों के 1600 करोड़ रुपये के बिजली के बिल माफ किए। उसके बाद सहकारी बैंकों के, लैंड मोरटगेज के, हरियाणा कल्याण निगम के, बैकवर्ड कल्याण निगम के लाई माई का सारा ब्याज भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने माफ करके बहुत ही सराहनीय कदम उठाया था और हमारी सरकार के यही कदम केन्द्र सरकार के लिए भी प्रेरणा स्रोत बने हैं। इसके अतिरिक्त हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने प्रदेश की जनता के हाउस टैक्स, चुल्हा टैक्स माफ किए और गेहूँ तथा धान के भाव भी बढ़वाये। इस प्रकार से हमारे प्रदेश में जो माहौल बना उससे केन्द्र सरकार ने प्रेरणा लेकर किसानों के 60 हजार करोड़ रुपये के कर्जे माफ किए जिसके लिए मैं हमारे मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ। सभापति महोदय, मैं हमारे मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि किसानों के तो कर्जे माफ हो गये हैं लेकिन हमारे प्रदेश में किसानों से भी दलित, पीड़ित, अपेक्षित वर्ग हैं जो भैंस, रेहड़ा, जूती, परचूनी आदि रोजगार के लिए लोन लेते हैं, उनका भी कर्जा माफ होना चाहिए। यदि केन्द्र स्तर पर इस तरह की पहल नहीं होती है तो हरियाणा सरकार को अपने स्तर पर इन वर्गों के कर्जे माफ करने चाहिएं। ऐसा करने पर बहुत उदार संदेश पूरे प्रदेश में और देश में जायेगा। इसी के साथ-साथ मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि कोआपरेटिव बैंकों का कर्जा जिन लैंड लैस लोगों को, दलित और हरिजन भाईयों को दिया जाता है वह रकम दस हजार रुपये से ज्यादा नहीं होती यानि की उन कर्जों पर दस हजार रुपये की लिमिट रखी हुई है। सभापति महोदय, आप सभी जानते हैं कि आज के दिन 25-30 हजार रुपये से कम में भैंस भी नहीं खरीदी जा सकती। जो यह दस हजार रुपये की लिमिट बनी हुई है यह बहुत पुरानी बनी हुई है इसलिए इसको दस हजार रुपये से बढ़ाकर कम से कम 50 हजार रुपये किया जाये ताकि गरीब हरिजन भाई कर्जा लेकर अपना काम धन्धा शुरू कर सकें। इसके साथ-साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि जो गरीब तबका है जो रोज़ कमाता है और रोज़ खाता है और जिस दिन दिहाड़ी नहीं मिलती तो उसे भूखा भी सोना पड़ सकता है। जिसको गेहूँ, चावल, तेल, दाल और सब्जी भी सभी चीजें मोल खरीदनी पड़ती हैं। महंगाई की चक्की में सबसे ज्यादा यही वर्ग पिस रहा है। इस वर्ग को आपने ढ़ाई साल पहले मिनीमम वेजिज़ 3510 रुपये करके बहुत बड़ी राहत प्रदान की थी। लेकिन अब ढ़ाई तीन साल में जो महंगाई बढ़ी है उसको देखते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस मिनीमम वेजिज़ को कम से कम 5 हजार रुपये मासिक किया जाये। इसके साथ ही जिस तरह से सरकार ने रेवेन्यु रिसीट्स के बारे में कहा है कि 2004-2005 में जो रेवेन्यु रिसीट्स 11,149 करोड़ रुपये थी वे तीन साल के बाद 2007-2008 में बढ़कर 19,630 करोड़ रुपये हो गई हैं जो

[श्री उदयभान]

कि 75 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है। यह इस बात को भी दिखाता है कि हमारी सरकार का वित्त प्रबन्धन कितना बेहतरीन है। इसके लिए भी मैं सरकार को बधाई देता हूँ। इसी प्रकार से प्लान बजट में भी तीन गुणा बढ़ौत्तरी की गई है और अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए 21.55 प्रतिशत का प्रावधान बजट में किया गया है। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। हमारी सरकार द्वारा ओलावृष्टि के नुकसान की भरपाई के लिए मौके पर जाकर एक-डेढ़ महीने के अन्दर जो तीन हजार, चार हजार और पांच हजार का मुआवजा देकर जो 208 करोड़ रुपये की राहत किसानों को प्रदान की गई उसके लिए भी यह सरकार बहुत-बहुत बधाई की पात्र है। जबकि पहली वाली सरकार द्वारा महज 200 रुपये, 300 रुपये और 400 रुपये मुआवजे के रूप में दिये जाते थे। इसके साथ ही सरकार द्वारा जो हरियाणा प्रदेश के अन्दर जो 11 हजार सफाई कर्मचारी नियुक्त किए जा रहे हैं उसके लिए भी मैं सरकार को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। चेयरमैन साहब, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, अपने पार्टी अध्यक्ष को और मंत्रिमण्डल सहयोगियों को अपनी कांग्रेस पार्टी के चुनाव घोषणा-पत्र का एक पैरा थोड़ा-सा पढ़कर सुनाना चाहूँगा कि श्री चौटाला के निरंकुश शासन में कमजोर वर्ग खास कर महिलाएं अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रही थी। कमजोर तबका अपने आपको सुरक्षित महसूस करे इसके लिए प्रत्येक प्रयास किया जायेगा। भूमिहीन अनुसूचित जाति के परिवारों में फालतू जमीन बांटने के लिए उपयुक्त कदम उठाये जायेंगे। अन्य कमजोर तबकों को भी जमीन दी जायेगी। अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग और कमजोर तबकों को आवासीय प्लाट उपलब्ध कराये जायेंगे। अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षित पदों के लम्बित कोटे को एक निश्चित समय सीमा के अन्दर निपटाया जायेगा। आरक्षण नीति को पूरी भावना के साथ लागू किया जायेगा। चेयरमैन साहब, इस सम्बन्ध में कई मामलों में सरकार द्वारा अभूतपूर्व निर्णय लिये गये हैं। जैसे लैंडलैस लोगों को आवासीय प्लाट देने का निर्णय लिया गया है यह हमारी सरकार की एक बहुत ही शानदार उपलब्धि है। इसके साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने शैड्यूल्ड कास्ट के छात्र-छात्राओं को पहली क्लास से लेकर हायर क्लासिज़ तक वजीफा देने का क्रांतिकारी कदम उठाकर एक अभूतपूर्व निर्णय लिया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के इस बेहतरीन कार्य को आने वाली पीढ़ियां कभी भुला नहीं पायेंगी। इसके लिए भी मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय की दिल से बार-बार सराहना करता हूँ। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार से 'इंदिरा गांधी पेयजल योजना' के तहत 8 लाख दलित परिवारों को मुफ्त पानी का कनैक्शन और 200 लीटर की पानी की टंकी दी गई है यह भी सरकार की एक शानदार उपलब्धि है। इसके साथ ही हमारी पुलिस कांस्टेबल के बी-1 के टैस्ट में रिजर्वेशन की मांग थी जिसको माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मान लिया है। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहूँगा। इसके अलावा हमारी एक बहुत पुरानी मांग थी जिसे हम प्रत्येक सैशन में उठाते रहे थे और वह मांग थी 85वें संविधान संशोधन को लागू करने की। इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 6 दिसम्बर, 2006 को घोषणा की कि 85वां संविधान संशोधन हरियाणा में लागू कर दिया जायेगा। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको मंत्री परिषद् में भी रखा और उसे पूरी भावना के साथ लागू करने का एलान किया। लेकिन कुछ तो अधिकारियों के कारण और कुछ अन्य कारणों से उसमें एक लाईन जोड़ दी गई कि वह 16 मार्च, 2006 से लागू होगा। जबकि वह 17 जून, 1995 से लागू होना चाहिए था और इस प्रकार 11 साल की सीनियोरिटी एक लाईन ने खत्म कर दी। इसकी वजह से किसी को कोई

लाभ नहीं हुआ। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहूँगा कि इस 85वें संविधान संशोधन को पूरी भावना के साथ जिस भावना से इसको लागू करने की घोषणा की गई थी उसी के अनुरूप इसको 17 जून, 1995 से लागू किया जाये ताकि उसका समुचित लाभ सम्बन्धित लाभार्थियों को मिल सके। इसमें सबसे बड़ी बात बैकलॉग की है। जो हमारी रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके बारे में आपने बार-बार तीन साल पहले शुरू से ही राज्यपाल के पहले अभिभाषण में भी, बजट सैशन में भी और चुनाव घोषणा पत्र में भी यह वायदा किया था कि हम बैकलॉग को पूरा करेंगे लेकिन हर विभाग में शैड्यूल्ड कास्ट का और बैकवर्ड क्लासिज का बैकलॉग पड़ा हुआ है। हर विभाग में बैकलॉग दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अब जो गैस्ट टीचर कंट्रैक्ट बेसिज पर लगाये गये हैं उनमें तो शैड्यूल्ड कास्ट के साथ पूरी तरह से अन्याय हुआ है और उनको पूरा कोटा नहीं मिला। **(इस समय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि सरकारी, अर्ध-सरकारी और बोर्ड/कारपोरेशनों में शैड्यूल्ड कास्ट के 30 हजार पद खाली पड़े हुए हैं। इस बैकलॉग को पूरा किया जाये।

श्री अध्यक्ष : उदयभान जी, आप वाईंड-अप करें।

श्री उदयभान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि इस बैकलॉग को पूरा करने के लिए कोई स्पेशल ड्राईव चला कर एक निश्चित समयावधि में पूरा करने का कष्ट करें। जिस तरह से आपने एस०सीज०/बी०सीज० के लिए क्रांतिकारी कदम उठाये हैं उस बात को ध्यान में रखते हुए इस बैकलॉग को पूरा करने के लिए कोई सकारात्मक कदम उठाए जायें। रोस्टर प्रणाली को भी सख्ती से लागू किया जाये। इंजीनियरिंग कॉलेजों तथा अन्य प्राईवेट संस्थानों में जिनमें एम०बी०ए० व एम०सी०ए० वगैरह की पढ़ाई की जाती है, वहां पर रिजर्वेशन पॉलिसी को कंसीडर नहीं किया जाता। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इन संस्थानों में भी दाखिले के समय रिजर्वेशन पॉलिसी को लागू किया जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए दो-तीन बातें ही और बताना चाहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री जी जब होडल में गये थे तो उन्होंने बहुत सी घोषणाएं की थी। उनमें से बहुत सी घोषणाएं पूरी हो गई जबकि कुछ बाकी हैं। जैसे मिनी सैक्रेटेरिएट का काम बहुत अच्छा चल रहा है, होडल में सीवरेज का काम चल रहा है, पानी का काम चल रहा है, आई०टी०आई० का तथा सड़कों का काम भी चल रहा है। लेकिन कुछ घोषणाएं अब भी बाकी हैं। पी०एच०सी० सिहोर का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। 18 दिसम्बर, 2005 को यह घोषणा की गई थी। 2 साल हो गये लेकिन अभी तक यह काम पूरा नहीं हुआ है। हसनपुर में यमुना पुल का काम है, पुलिस स्टेशन का है तथा हॉस्पीटल बनाने के काम की इत्यादि की कुछ घोषणाएं हैं जिनको पूरा करवाने की कृपा करें। हसनपुर का नगरपालिका का दर्जा बहाल करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : उदयभान जी, बाकी आप लिखवा कर भिजवा दें उनको पढ़ा ही मान लिया जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, आप हमें बोलने का मौका दीजिये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा जी, आप बजट पर बोल लेना। दो घण्टे आपके लीडर बोल कर चले गये। आप शोक प्रस्ताव पर भी बोल चुके हैं। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाह रहा था कि सत्ता पक्ष के जो साथी हैं वे तो सरकार की सराहना ही करेंगे, सरकार को सही रास्ता नहीं दिखायेंगे लेकिन जो विपक्ष के साथी हैं वे पूरी तरह से सही बात कहेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा जी, आप बजट पर बोल लेना। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राधे श्याम शर्मा अमर : अध्यक्ष महोदय, सही बात कहेंगे तभी रास्ता दिखायेंगे, झूठी बातों से क्या रास्ता दिखायेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने जब डॉ० सीता राम जी को बोलने के लिए कहा तो आपके नेता ने कहा कि यह क्या बोलेंगे? यह रिकॉर्ड की बात है। तब आप कुछ बोले ही नहीं। आपके लीडर दो घंटे बोल कर चले गये।

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, गर्मा गर्मी में ऐसी बातें हो जाती हैं। आपने राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने के लिए मुझे कहा ही नहीं। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, * * * * * *

श्री अध्यक्ष : यह रिकॉर्ड न किया जाये।

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, माननीय इन्दौरा जी से कहना चाहूँगा कि केवल खबरें बनाने के लिए इस तरह की बातें न कहें।

श्री अध्यक्ष : डॉ० साहब, आपके लीडर दो घण्टे बोल कर चले गए लेकिन उन्होंने सरकार की कोई विफलता नहीं बताई (विघ्न)।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, * * * * * *

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि इन्दौरा साहब एक बहुत ही तजुर्बेकार आदमी हैं। सदन के माननीय नेता महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हुई बहस का जवाब देने के लिए हाउस में खड़े हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, अगर इनकी मन्शा यही है कि आज वाकआउट करके अखबार की खबर बनाना है तो अलग बात है (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, आज ये लोग केवल अखबार की खबर बनाना चाहते हैं तो अलग बात है वरना इनको बैठकर रिप्लाई सुनना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा साहब, आप लोग अपनी सीटों पर बैठें और महामहिम गवर्नर साहब के अभिभाषण पर लीडर ऑफ दि हाउस का रिप्लाई सुनें। डॉ० इन्दौरा इस रिप्लाई में से आपका जो कुछ भी रह जाएगा वह आप बजट पर बोल लेना। मैं आप अकेले को बजट पर बोलने के लिए आधे घण्टे का समय दे दूँगा अभी आप बैठें।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now, Hon'ble Chief Minister will give reply.

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, इस महान सदन में हरियाणा के महामहिम राज्यपाल किदवई जी ने 7 मार्च, 2008 को जो प्रभावी अभिभाषण दिया, हरियाणा के लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरते हुए उन्होंने जो बातें कहीं उनके लिए मैं उनका धन्यवाद करने के लिए आज खड़ा हुआ हूँ। इस अभिभाषण में उन्होंने हर मुद्दे को जोड़ा है। हरियाणा की कांग्रेस पार्टी की सरकार की नियति और नीति आज हर गरीब, पिछड़े और अनुसूचित जाति, साधारण किसान व आम आदमी के विकास पर केन्द्रित है। यह हमारे राज्य के उन वर्गों पर केन्द्रित है जो समाज में पिछड़े हुए हैं। ईमानदारी, मेहनत और नेकनीयत से हमने न केवल अपने वायदों को पूरा किया है बल्कि जो वायदे नहीं किये थे उससे भी बढ़ कर हमने सारे कार्य किये हैं। स्पीकर सर, तीन साल पहले जब हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में आई तो मेरे साथियों ने एक सपना देखा कि हमने अपने प्रदेश को देश में नम्बर एक का प्रदेश बनाना है और उसके लिए हमने काफी फैसले किये और हर क्षेत्र में सफलताएं प्राप्त कीं। जैसे प्रति व्यक्ति निवेश की बात है जब हमारी सरकार सत्ता में आई तो हरियाणा प्रदेश पूरे देश में 14वें नम्बर पर था। स्पीकर सर, यह बात मैं नहीं कह रहा बल्कि यह सैंट्रल फोरम मॉनिटरिंग ऑफ इण्डिया इकोनोमी ने सर्वे करके कहा है। हम 14वें नम्बर पर थे लेकिन आज हरियाणा प्रदेश में निवेश के मामले में देश भर में नम्बर वन पर है। **(इस समय मेजें थपथाई गईं)** स्पीकर सर, इसी प्रकार से वित्तीय प्रबन्धन में हमारा हरियाणा प्रदेश सर्वश्रेष्ठ राज्यों में से एक है। इसी प्रकार से प्रति व्यक्ति आय में हमारा प्रदेश देश भर में दूसरे नम्बर पर है और गोवा से पीछे है। गोवा में टूरिस्ट इन्कम है। इसी प्रकार से हमारा प्रदेश दूध की उत्पादकता में पहले पंजाब से पीछे था आज दूध के उत्पादन में हरियाणा प्रदेश देश भर में नम्बर वन है। **(इस समय मेजें थपथाई गईं)** स्पीकर सर, इसी प्रकार से गेहूँ के उत्पादन में हमारा प्रदेश देश भर में नम्बर एक पर है। अध्यक्ष महोदय, तरक्की का जो आधार होता है वे वित्तीय साधन होते हैं। जब तीन साल पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी उससे पहले वर्ष 2004-05 में हमारी सरकार आने से पहले सरकार का जो बजट था मैं उसकी चर्चा करना चाहूँगा। हमारे विपक्ष के साथी बैठे हुए हैं जब इनकी सरकार थी तो इनका जो प्लांड बजट था 2305 करोड़ रुपये था और इस में से इन्होंने कुल 2108 करोड़ रुपये खर्च किये। स्पीकर सर, मुझे यह कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि आज वर्ष 2008-09 में हमारा जो प्लांड बजट है वह 300% बढ़ गया है और हमारा प्लांड बजट 6650 करोड़ रुपये हो गया है जो कि सरकार की नीयत और नीति का जीता जागता सबूत है। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का हर पन्ना प्रदेश की खुशहाली की कहानी कहता है। उन्होंने कहा कि हर पन्ने में हमारी खुशहाली है और प्रदेश में चारों तरफ गहमा-गहमी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आलोचना में विश्वास नहीं करता लेकिन मुझे इस बात की हैरानगी है कि जैसे अभी डॉक्टर इन्दौरा साहब भी कह रहे थे और पहले श्री चौटाला जी भी बोल गये। अध्यक्ष महोदय, हमारे हरियाणा में बसन्त बहार आ रही है लेकिन मेरे विपक्ष के भाईयों को यह पतझड़ क्यों लग रही है, पता नहीं इसका क्या कारण है। ये लोग सिर्फ सुर्खियां बनाने के चक्कर में रहते हैं। इन लोगों को तो सरकार के कार्यों की सराहना करनी चाहिए। इनको चाहिए कि इस बारे में ये कोई पैरामीटरज तय करें, यहां हाउस में बैठकर बहस करें और तथ्य सबके सामने रखें तो सारी सच्चाई सामने आएगी लेकिन अखबार की सुर्खियां बनाने से कुछ नहीं होगा। स्पीकर सर, जैसे हमारे पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर ने कहा कि अखबार की सुर्खियां बनाना ही विपक्ष का काम नहीं होता है। विपक्ष का काम कंस्ट्रक्टिव सलाह देना और सही बात कहना होता है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने स्वच्छ और पारदर्शी प्रशासन प्रदान

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]
किया है इसलिए हम किसी ढोंग या प्रपंच की सहायता नहीं लेते जबकि हमारे साथी लोकहित का जामा पहन कर अपने स्वार्थ सिद्ध करते हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, चेहरे पर चेहरा लगाकर ठगने वालों को समझना चाहिए कि सच्चाई को कोई छिपा नहीं सकता है। चेहरे पर चेहरा लगाकर सच्चाई छिप नहीं सकती है। वह तो सामने आएगी। सच्चाई नैकेड होती है। This is an untruth must hide behind the clock of curtains. Truth, however, must go naked it. राज्य के लिए सबसे बड़ी चीज है शान्ति और सुरक्षा। यह सब आपके सामने है। आप निवेश लगाएं। आज किस प्रकार से हमारा प्रदेश तरक्की कर रहा है, यह सब आपके सामने है। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रान्त के सभी वर्गों की तरक्की से जुड़े हुए सभी बिन्दुओं पर प्रकाश डालना चाहूँगा। सबसे पहले मैं कृषि जगत के विकास के बारे में कहना चाहूँगा। इसका विकास करना हमारा धर्म है। वर्ष 2008 का जो केन्द्रीय बजट पेश हुआ है और उसके बारे में मान साहब ने भी कहा है कि यह बहुत बढ़िया बजट पेश हुआ है। अध्यक्ष महोदय, यह ऐतिहासिक बजट श्रीमती सोनिया गांधी जी और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पेश किया गया है। इस बजट में किसानों का 60 हजार करोड़ रुपये का लोन माफ किया गया है यह एक ऐतिहासिक कदम है। आज तक के इतिहास में इस फैसले का कोई मुकाबला नहीं है। मैं अपनी तरफ से और अपने साथियों की तरफ से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का और श्रीमती सोनिया गांधी जी का धन्यवाद करता हूँ। मुझे उम्मीद थी कि हमारे विपक्ष के साथी पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी सदन में आएंगे लेकिन मुझे नहीं पता वे क्यों नहीं आए। मुझे नहीं पता कि वे किसानों के हितों की बात करते हैं। उन्होंने सदन में चर्चा के दौरान क्रिटिसीज्म किया है, उन्होंने कहा है कि ऋण माफी की वजह से डिफाल्टर्ज बढ़ेंगे और दूसरी तरफ उन्होंने अपने पिता के द्वारा वर्ष 1987-88 तथा वर्ष 1990 में ऋण माफ किया था उसका गुणगान किया था। उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि केन्द्र की सरकार ने और हरियाणा की सरकार ने जो ऋण माफ किया है ये इस बारे में हां या ना में जवाब दें कि ये उसके पक्ष में हैं या नहीं हैं। एक तरफ तो ये हक की बात करते हैं और दूसरी तरफ मुखालफत करते हैं। इनकी यह बात हमारी समझ में नहीं आई है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, हम ढकोसलों के खिलाफ हैं, जो हकीकत में काम करते हैं उनके खिलाफ नहीं हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : ढकोसले तो आपके सामने आ रहे हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं कि डिफाल्टर बढ़ेंगे। (शोर एवं व्यवधान) यह चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का ब्यान है।

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है कि इस ऋण माफी के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं इनको उन दोनों के बारे में बताना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

Sh. Bhupinder Singh Hooda : I am not yielding. (शोर एवं व्यवधान) सदन की कुछ गरिमा होनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : When the leader of the House is speaking there should not be any interruption at all.

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : इनको कुछ तो सुनना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये ऋण माफी की स्कीम

जो केन्द्र की सरकार ने दी है, ये उसके हक में है या खिलाफ में है। ये हां या ना में जवाब दें। इससे सारी बात स्पष्ट हो जायेगी। चौटाला जी जब विपक्ष में थे और उसके बाद मुख्यमंत्री बने थे और यह बात आम कहते थे और लोगों को गुमराह करते थे कि न मीटर होगा और न रीडिंग ली जाएगी। तुम बिजली के बिल न दो। इनके सत्ता में आने के बाद कण्डेला में जो हुआ वह सब जानते हैं और वहां पर लोगों के ऊपर गोलियां चलवाई। अध्यक्ष महोदय, मैं चौटाला जी के बारे में कहना चाहूँगा कि—

वायदा तो कर लिया लेकिन यह नहीं सोचा तुमने,
वायदा करना तो आसान है लेकिन वायदे की वफा मुश्किल है।

अध्यक्ष महोदय, जब वे सदन में बोले तो उस समय मैं यहां पर नहीं था लेकिन मुझे यह जरूर पता चला कि उन्होंने क्या बोला है। अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि—

मेरा जमीर बहुत है मेरी सदा के लिए
तूं तो नसीयत न कर खुदा के लिए।
तू क्या नसीयत करेगा खुदा के लिए,
मेरा जमीर है मेरी सदा के लिए॥

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सदन में बताना चाहूँगा कि चौधरी देवी लाल जी ने जो कर्जे माफ किए थे उसके बारे में इन्होंने सदन में चर्चा की। उस वक्त उन्होंने 34 करोड़ रुपये कर्जे माफ किए गए थे जबकि ये हजारों करोड़ों रुपये के कर्जे माफ किए गए बता रहे थे। मैं सदन में यह कहना चाहूँगा कि उस वक्त 34 करोड़ रुपये का ही लोगों को फायदा हुआ था। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। स्पीकर सर, मैं मुख्यमंत्री जी की कही हुई बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरे पास इनकी कही हुई बात का रिकॉर्ड है। (Interruptions)

Shri Randeep Singh Surjewala : The leader of the House has not yielded.

Dr. Sushil Indora : He is not yielding but the facts are there.

Shri Randeep Singh Surjewala : You were given the opportunity to tell the facts but it does not mean you will continue to speak. (Interruptions)

श्री अध्यक्ष : डॉक्टर साहब, आप इस तरह खड़े न हों, आप बैठें।

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, मैं इन्हीं का एक शेर कहना चाहता हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का ही गवर्नर ऐड्रैस पर किया हुआ भाषण है। आप चाहें तो रिकॉर्ड निकलवाकर देख लीजिए। ये अब 34 करोड़ रुपये की बात कह रहे हैं जबकि इन्होंने ही अपने भाषण में कहा कि चौधरी देवीलाल जी ने 2830 करोड़ रुपये माफ किए थे। स्पीकर साहब, यह लिखा हुआ है। यह 2005-2006 में इनका दिया हुआ भाषण है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, यह एक क्लैरीकल मिस्टेक का सहारा ले रहे हैं।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, ये आज सिर्फ 34 करोड़ रुपये कह रहे हैं जबकि इन्होंने पहले कुछ और कहा है। इन्होंने अपने भाषण में जोर देकर कहा है कि उस समय 2830 करोड़ रुपये के कर्ज माफ हुए हैं इसलिए इस बात की भी इंवैस्टीगेशन करायी जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : डॉक्टर साहब, आप बैठें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैंने ऑन दि फ्लोर ऑफ दि हाउस यह नहीं कहा है। इन्दौरा जी मेरे साथी हैं और ये पार्लियामैंट में भी रहे हैं। इनको हाउस की गरिमा को बनाए रखना चाहिए। इनको सुनने की सब्र रखनी चाहिए। लोगों ने इनका झूठ बहुत सुन लिया इसलिए अब इनको सच्चाई सुनने की आदत डालनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा जी, इस तथ्य के बारे में एक कमेटी बना दी गयी है। वह कमेटी यही चीज वैरीफाई करेगी। इस कमेटी की मीटिंग 19 तारीख को रख दी है। वहां पर आप अपनी ये बातें कह लेना।

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर साहब, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कही हुई बात कह रहा हूँ। मैं सदन के सम्मान का पूरा ध्यान रखता हूँ। मैं सदन के नेता का और चेयर का भी सम्मान करता हूँ लेकिन जो बात है उसको सामने रखने की जिम्मेवारी मेरी है।

श्री अध्यक्ष : डॉक्टर साहब, सदन के पटल पर दो बातें आयीं हैं। एक तरफ तो चौटाला साहब और आप कह रहे हो और दूसरी तरफ इधर से पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर और सदन के नेता अपनी बात कह रहे हैं तो उसकी वैरीफिकेशन के लिए ही कमेटी की मीटिंग 19 तारीख को बुलाई गई है। वहां पर आप अपने ऐवीडैंस रखना कि कौन झूठा है कौन क्या है किसने मान मर्यादा तोड़ी है। वहां पर पता लग जायेगा। प्लीज, अब आप बैठें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास सारा रिकॉर्ड है, तथ्य सामने हैं। 1987-88 में किसानों के कर्जे माफ होने से कितना लाभ हुआ है वह मैं आपको बता देता हूँ। 34.31 करोड़ रुपये का कुल लाभ हुआ है। मेरे पास इस बात का रिकॉर्ड है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक हमारी सरकार का सवाल है, हमारी सरकार ने तो 1600 करोड़ रुपये बिजली के बिलों की माफी योजना की एक स्कीम दी। इस स्कीम से 6,19,137 उपभोक्ता परिवारों को तकरीबन हजार करोड़ रुपये का लाभ हुआ है। इसी प्रकार से जैसा उदयभान जी ने कहा, सहकारी बैंकों के कर्ज का ब्याज माफ करने के लिए छोटे दुकानदारों एवं कामगारों को 130 करोड़ रुपयों का लाभ पहुँचाने की स्कीम मौजूदा सरकार ने चलायी। इस स्कीम का लाभ भी तकरीबन 3 लाख 64 हजार कर्जदारों ने 450 करोड़ रुपयों का उठाया है। अध्यक्ष महोदय, जो किसान कोऑपरेटिव बैंकों का लोन लेते थे और न देने की स्थिति में उनको जीप में बिठाकर ले जाते थे और जेल में रखते थे। जेल में वह जितने दिन रहते थे उतने दिन ही उसकी खायी हुई रोटियों का खर्चा भी उसके कर्ज में जोड़ दिया जाता था। अध्यक्ष महोदय, किसानों की गिरफ्तारी का ऐसा काला कानून था लेकिन इस काले कानून को भी मेरी सरकार ने खत्म कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, मौजूदा कांग्रेस सरकार ने सहकारी फसल ऋणों के ब्याज की दर जो पहले 11 प्रतिशत किसानों को देनी होती थी उसको अब 7 प्रतिशत पर किया है। अब सात प्रतिशत ब्याज दर पर किसानों को लोन दिया जा रहा है। यह

हमारी किसानों के प्रति कटिबद्धता है।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, सदन की मांग तो चार प्रतिशत की है इसलिए मुख्यमंत्री जी चार प्रतिशत ब्याज की दर की घोषणा करें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : लेकिन इनके राज में तो यह ब्याज की दर 11 प्रतिशत थी लेकिन हमने यह दर चार प्रतिशत तक घटा दी। डॉक्टर साहब, आप 11 प्रतिशत में से 4 प्रतिशत दर घटाओ।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी इस ब्याज दर को चार प्रतिशत पर ले आएं।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, जब सदन के नेता बोल रहे हों तो इनको इस तरह से इंट्रप्शन नहीं करनी चाहिए।

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, जब हमारे नेता बोल रहे थे तो ये सारे लोग बड़ी वाहवाही लूटवा रहे थे। यह क्या मामला हुआ।

श्री अध्यक्ष : लेकिन आपके नेता तो सदन के नेता नहीं है। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर साहब, बड़ी खुशी होती अगर कोई विपक्ष के नेता होते लेकिन इनके तो उतने नम्बर भी नहीं हैं। हर कोई फ्री फोर आल है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : डॉक्टर साहब, आप हाउस की गरिमा बनाए रखें क्योंकि सारी कार्यवाही की वीडियोग्राफी भी हो रही है। आप हाउस की गरिमा को लांघ रहे हैं। When the leader of the House is on his legs, you should listen patiently. जब आपको बता दिया कि आप आधा घंटा बोल लेना और अभी आप प्वायंट्स नोट कर लें इसलिए अब आप बैठें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, ये तो अपना टेप करके उनको सुनाने की बात कर रहे हैं। इनका और कोई मकसद नहीं है। आपने बहुत सारी झूठी बातें कह लीं हैं अब आप सच्ची बातें सुनने का दम रखो। जहां तक न्यूनतम समर्थन मूल्य का सवाल है। उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि वर्ष 2003-04 में जब इन साथियों की सरकार थी तो गेहूँ का समर्थन मूल्य 630 रुपये था और अब हमारे समय में वर्ष 2007-08 में एक हजार रुपये प्रति क्विंटल रेट है। इस प्रकार इसमें 370 रुपये प्रति क्विंटल की दर से इज़ाफा किया है। इनकी सरकार ने 5 साल के कार्यकाल में मात्र 40 रुपया बढ़ाया था और हमारे कार्यकाल में 370 रुपये अब तक बढ़ चुके हैं। धान में 580 रुपये रेट वर्ष 2003-04 में था वह हमने 775 रुपये किया, इसमें 195 रुपये का इज़ाफा किया, इनके समय में 40 रुपये मात्र का इज़ाफा हुआ था। इसी प्रकार से सामान्य धान का रेट 550 रुपये था हमने अपने कार्यकाल में बढ़ाकर 695 रुपये किया और इसमें 145 रुपये इज़ाफा किया। इसी प्रकार से गन्ने का रेट 110 रुपये था जिसे बढ़ाकर 138 रुपये किया और इस प्रकार 28 रुपये रेट बढ़ाया। इसी प्रकार से बाजरे में 95 रुपये, तिलहन में 470 रुपये, जौ में 145 रुपये, चने में 375 रुपये, कपास में 105 रुपये और सरसों में 200 रुपये का इज़ाफा किया। यह आपके समक्ष है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से मैं साथियों को याद दिलाना चाहूँगा कि जो भूमि अधिग्रहण की बात हुई है। इनकी सरकार के समय में भूमि अधिग्रहण का मुआवजा 50 हजार रुपये से लेकर 2 लाख रुपये मिलता था। आज ही इस बारे में जैसा कि क्वैश्चन

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

ऑवर में बताया गया। हमारी सरकार ने 20 लाख रुपये, 16 लाख रुपये पर एकड़ स्थान के अनुसार सोलेशियम के साथ लाभ दिया। 26 लाख, 20.80 लाख रुपये पर एकड़ व 10.40 लाख रुपये पर एकड़ मुआवजा दिया। इसके अलावा जो भी सरकारी काम के लिए जमीन अधिग्रहण होगी उसको 15 हजार रुपये प्रति वर्ष प्रति एकड़ के हिसाब से 33 साल तक देंगे और हर साल उसमें 500 रुपये की बढ़ौत्तरी देंगे। एस०ई०जेड० के इनके समय में सैक्शन 4 और सैक्शन 6 में नोटिस हुये थे, उसमें अब हमारी सरकार ने यह फैसला किया है कि कोई भी जमीन अधिग्रहीत होगी तो उसका 33 साल तक 30 हजार रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष मुआवजा किसान को देंगे और उसमें 1 हजार रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से इजाफा होगा। इस बारे में हमारे एक ही फैसले से किसान को कितना लाभ हुआ है, यह आपको बताना चाहूँगा। कुण्डली, मानेसर, पलवल ऐक्सप्रेस वे का जो मेरी सरकार की कैबिनेट का फैसला हुआ था उस फैसले की कॉपी मेरे पास है। इसमें लिखा है कि— "The cost of land acquisition is expected to be Rs. 170.80 crores." About 3450 acres of land जो जमीन इन्होंने ऐक्वायर की थी उसका कुल मुआवजा 167 करोड़ रुपये उस समय आंका गया था, यह सरकारी पत्र में लिखा है और हमारी सरकार ने आते ही उसका जो फ्लोर रेट फिक्स किया उससे उनको 630 करोड़ रुपये की राशि मिली। इस प्रकार किसानों को सरकार के एक ही फैसले से 500 करोड़ रुपये का लाभ हुआ। इनके राज में किसानों को और गरीबों को लूटा गया था। (शोर एवं व्यवधान) प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। अब मैं सिंचाई की बात कहना चाहता हूँ। मेरे साथियों ने नहरी पानी की कमी की चर्चा की और हमने उस कमी को पूरा करने के लिये पूरे प्रदेश में बहुत सारी नहरी पानी की परियोजनाएं चलाईं। जिनके बारे में अलग-अलग चर्चा भी हुई है। एक हांसी-बुटाना लिंक नहर है जिसका मकसद यह है कि जो पानी उपलब्ध है उसका समान बंटवारा किया जाए ताकि जिसका जितना हक है उसको उतना पानी मिले। उस नहर का 98 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है और उसके पूरा हो जाने के बाद 2 हजार क्यूसिक पानी उस नहर में आएगा और उसकी लागत 354 करोड़ रुपये के करीब थी और ये साथी कहने लगे कि जब तक यह बनकर तैयार होगी, इसकी इतनी ही लागत और हो जाएगी। जब 98 प्रतिशत काम अगर पूरा हो गया है तो लागत और बढ़ाने का सवाल ही नहीं है। इस नहर को बनाने की बड़े जोर-शोर से मुखालफत हुई और काफी कुछ कहा गया। एक पेपर की कटिंग मेरे पास है जिसमें लिखा है कि 'नई नहर खोदने से आंतरिक गृहयुद्ध छिड़ जायेगा, अजय'। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में पानी के समान बंटवारे की बात हो रही है और यह कह रहे हैं कि गृहयुद्ध छिड़ जायेगा। अगर इंसाफ पर गृह युद्ध होना है तो मैं पूर्व मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला जी से एक ही सवाल पूछता हूँ कि आप बताएं कि क्या आप नहर बनाने के हक में है या खिलाफ हैं, स्पष्ट करें। इस बात का जवाब ये अपने आप दे दें।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण

(श्री ओम प्रकाश चौटाला द्वारा)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मेरी पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन है। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने जमीन अधिग्रहण के मामले को लेकर इस सदन को गुमराह करने का काम किया है। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : आप मेरे इस सवाल का जवाब दे दीजिए कि आप इस नहर के बनाने के हक में हैं या नहीं। अध्यक्ष महोदय, गुमराह तो ये अपने आप करते रहे हैं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : आप मेरी बात सुनिये, आप बैठ जाईये।

श्री अध्यक्ष : आपकी पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन क्या है?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, हांसी-बुटाना लिंक नहर की बात हो रही है, ये हां या ना में जवाब दें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : आप सुनने की कोशिश तो कीजिए।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : आप सही बोलेंगे तो सुनेंगे।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मुझे हैरानी तो इस बात की है कि न तो हमें बोलने दिया जाता है (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, इनको सुनने की हिम्मत रखनी चाहिए। (विघ्न)

Mr. Speaker : Chautala ji, you are on your legs for personal explanation. What is your personal explanation? (Noise and Interruptions). Why you are wasting the time of the House? (Noise and Interruptions).

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे डांट रहे हैं या मेरी बात सुन रहे हैं। लीडर ऑफ दि हाउस ने हाउस को गुमराह किया है कि हमारी सरकार के वक्त में 5, 10 या 15 हजार से दो लाख रुपये तक का मुआवजा दिया। यह तो रिकॉर्ड की बात है। अब तक हमारी सरकार ने लोगों को जमीन का कम्पैंसेशन दिया उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार के वक्त में गुड़गांव के चार गांव की जमीन का कम्पैंसेशन 29 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को दिया गया था। भाव किसानों को तब दिए जाते हैं जब जमीन की कीमत बढ़ जाती है तो किसानों को भी उसी हिसाब से कम्पैंसेशन दिया जाता है। जमीन के भाव के मुताबिक किसानों को भाव मिलेगा। दूसरा इन्होंने नहर बनाने का जिक्र करने का काम किया। (विघ्न)

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भ)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, जो इन्होंने बात कही है उसके बारे में मैं आपके माध्यम से श्री चौटाला जी को बताना चाहूँगा कि मेरे पास इनकी सरकार के समय की कैबिनेट मीटिंग का सबूत है इनकी सरकार के समय में के०एम०पी० एक्सप्रैस हाईवे बनाने के लिए 3450 एकड़ जमीन की कीमत किसानों को 170 करोड़ रुपये दी गई। इन्होंने लिखकर दिया हुआ है। जबकि हमारी सरकार ने उसी जमीन का किसानों को कम्पैंसेशन 630 करोड़ रुपये दिया है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : ठीक है आप भी सबूत के आधार पर कह रहे होंगे, मैं भी सबूत के आधार पर कह रहा हूँ कि कीमतें बढ़ने के बाद कम्पैंसेशन भी बढ़ जाता है यह स्वाभाविक हैं (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : एक दिन में 500 करोड़ रुपये बढ़ गये क्या ?

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अरे, आप सुनने की हिम्मत तो रखो। कभी एक सदस्य खड़ा होता है कभी दूसरा खड़ा हो जाता है। कोई बिना बोले बोलना शुरू कर देता है (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितने अच्छे काम किए हैं उनके लिए हमें चौटाला जी से और उनकी पार्टी से सर्टिफिकेट लेने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि आज हरियाणा ही नहीं सारा देश इनकी वाह-वाह कर रहा है। जहां तक चौटाला जी का सवाल है इनकी पार्टी का जो नियम है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि एक दफा इनकी पार्टी की मीटिंग हो रही थी जिसमें बड़े-बड़े नेता थे मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, दलाल साहब का प्वायंट ऑफ ऑर्डर किस बात के लिए हो रहा है ? (विघ्न) ये मुख्यमंत्री जी की बात का जवाब दें न कि हमारी पार्टी के बारे में बतायें। ये हमारी पार्टी के आंतरिक मामले में दखल न दें। स्पीकर सर, ये क्या कहना चाहते हैं ? यह स्पष्ट बतायें कि हमारी पार्टी के बारे में ये क्या कहना चाहते हैं। इस तरह की उलूल-जलूल बात करके ये सदन को क्यों गुमराह करना चाहते हैं। ये क्यों सदन का टाईम खराब कर रहे हैं ? (शोर एवं व्यवधान)

Shri Karan Singh Dalal : Speaker Sir, I am standing on a point of order. (Noise and Interruptions). ये मेरी बात सुनना नहीं चाहते। Speaker Sir, I want your protection. (Noise and Interruptions). अध्यक्ष महोदय, मुझे मेरी बात तो पूरी करने दें, क्योंकि यह बहुत जरूरी बात है। इनकी पार्टी का नियम यह है कि लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है।

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, दलाल साहब, हमारी पार्टी के नियमों के ज्ञाता कब से हो गये ? (शोर एवं व्यवधान) इनको अपनी पार्टी की चिन्ता होनी चाहिए, ये हमारी पार्टी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं ?

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत चौटाला साहब और इनकी पार्टी के विधायकों को यह कहना चाहता हूँ कि जो इनकी पार्टी के नियम हैं कि लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कहते हैं कि लोगों को तो बहकाने की जरूरत है। ये तो लोगों को बहकाने में लगे रहते हैं। सदन के अन्दर और सदन के बाहर इनको बाज आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आप बैठिये।

16.00 बजे

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदन के नेता ने स्पष्ट कहा है कि कुण्डली मानेसर एक्सप्रैस हाइवे के लिए 3450 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था, हमारे पास मंत्रीमंडल की बैठक की प्रोसीडिंग्स मौजूद हैं, जिसको मुख्यमंत्री महोदय जी ने पढ़कर सुनाया है उसमें स्पष्ट है कि कैबिनेट ने यह कहा है कि 170 करोड़ रुपये

मुआवजा दिया जाएगा उसके जवाब में माननीय चौटाला जी ने पर्सनल एक्सप्लेनेशन देते हुए कहा है कि कीमतें बढ़ने के साथ-साथ जमीन की कीमतें और मुआवजे बढ़ जाते हैं। शायद वे समझ नहीं पाए और शायद हम अपनी बात उन तक पहुँचा नहीं पाते क्योंकि अध्यक्ष महोदय, कई बार वेवलैंथ नहीं मिलता। उनको मैं यह बताना चाहता हूँ कि उसी 3450 एकड़ जमीन जिसकी कीमत आपने दफा 4 और 6 लगाकर 170 करोड़ रुपये आंकी थी हमारी फ्लोर रेट नीति तय होने के बाद उसकी कीमत 650 करोड़ रुपये हो गई और 500 करोड़ का उसमें इजाफा हुआ, इसलिए सदन को गुमराह न करें और साफ बताएं कि आप हांसी बुटाना लिंक नहर के हक में हैं या हांसी बुटाना लिंक नहर के खिलाफ हैं। आप हर बार बात को घुमा लेते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

वित्त मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह) : अध्यक्ष महोदय, चौटाला साहब ये बात मान रहे हैं कि जब कीमतें बढ़ती हैं तो कम्पनसेशन बढ़ता है। 2005 तक तो कीमतें बढ़ी नहीं और हमारी सरकार आते ही कैसे कीमतें बढ़ गई, हमने कीमतें बढ़वाई। हमने फ्लोर रेट तय किए और जब फ्लोर रेट तय किए तो उसके हिसाब से 500 करोड़ रुपये का एकदम इजाफा हो गया, इन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : इनकी सरकार ने किसानों को लूटा, हमने किसानों को आबाद किया है और हमने किसानों को पूरा कम्पनसेशन दिया है। सीधी सी बात है और कोई लम्बी चौड़ी बात थोड़े ही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : ठीक है मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि बरसों के बाद कीमतें बढ़ी हैं और मुझे तथ्यों पर आधारित कोई बात कहने में कोई संकोच नहीं है। अध्यक्ष महोदय, *******

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded.

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, खिसयानी बिल्ली खम्भा नोचे। चौटाला जी, आप हमारे बड़े भाई हैं, हम सम्मान से आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि आप हांसी बुटाना लिंक नहर के हक में हैं या उसके खिलाफ हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, *******

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सदन में इस तरह की बात करते हैं जो ठीक नहीं है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, *******

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded.

सिंचाई मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : अध्यक्ष महोदय, ओम प्रकाश चौटाला जी का अमर उजाला में ब्यान आया है कि हांसी बुटाना लिंक नहर की जरूरत नहीं—चौटाला। यह ब्यान इनका सैशन के दौरान आया है।

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : इनके तो पता नहीं क्या-क्या ब्यान आ रहे हैं, इन्होंने तो विधान सभा के रिकॉर्ड में कह रखा है कि मैं जब तक जीऊंगा मुख्यमंत्री रहूँगा और आज ये इधर बैठे हैं तो पता नहीं ये बैठे हैं या इनका भूत इधर बैठा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई के बारे में सदन में चर्चा कर रहा था। मैंने एक सवाल माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी के सामने रखा था उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे जो सवाल कर रहा हूँ उसका ये हां या ना में जवाब दें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : आप बैठो, मैं जवाब देता हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, अमर उजाला में ओम प्रकाश चौटाला जी का ब्यान छपा है कि—हांसी बुटाना लिंक नहर की जरूरत नहीं है, चौटाला। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : कौन चौटाला। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : ओम प्रकाश चौटाला का यह ब्यान है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : * * * (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : * * * (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील कुमार इन्दौरा : * * * (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded. (Noise & Interruption)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, चौटाला जी इस बात का जवाब दे दें कि ये हांसी बुटाना लिंक नहर के पक्षधर हैं या नहीं हैं। (शोर एवं व्यवधान) दूसरा ये स्पष्ट जवाब दें कि इनके पुत्र ने यह ब्यान दिया था या नहीं दिया कि यदि हांसी बुटाना लिंक नहर बनेगी तो वे हरियाणा में गृह युद्ध करवा देंगे। अध्यक्ष महोदय, ये लोग हमेशा हरियाणा प्रांत के लोगों को बरगलाते हैं, बहकाते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : * * * (शोर एवं व्यवधान)

सदस्य का नाम लेना

श्री अध्यक्ष : चौटाला जी, आप सदन की गरिमा का ध्यान नहीं रखते। आप सदन के नेता को कैसे कह सकते हैं कि आप बैठो। (शोर एवं व्यवधान) How did you dare to talk like that. (Interruptions) You are doing knowingly when the matter is behind the shadow of your mental impotency.

डॉ० सीता राम : * * * (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Dr. Sita Ram, please sit down. Nothing is to be recorded.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : * * * (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : * * * (शोर एवं व्यवधान)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

Mr. Speaker : Dr. Sita Ram, I warn you.

डॉ० सीता राम : * * * (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Dr. Sita Ram, I name you. You may leave the House. (Interruptions)

(At this stage Dr. Sita Ram withdrew from the House.)

वाक-आऊट

श्री ओम प्रकाश चौटाला : हमारी बात नहीं सुनी जा रही इसलिए एज ऐ प्रोटैस्ट हम सदन से वाक आऊट करते हैं।

(इस समय सदन में उपस्थित इण्डियन नेशनल लोक दल के सभी सदस्य सदन से वाक-आऊट कर गए।)

श्री राम कुमार गौतम (नारनौंद) : अध्यक्ष महोदय, हमारी बगल में बैठे ये वे लोग हैं जिन्होंने पोलीटिकल आदमियों की छवि को धूल में मिला दिया। ये लोग प्रदेश की जनता का खरबों रुपये लूटकर खा गये। आपकी सी०बी०आई० न जाने कहां सो रही है? अगर सी०बी०आई० इनके खिलाफ जल्दी से कार्यवाही करती तो आज ये यहां न होते। इन लोगों ने पोलीटिकल लोगों की ऐसी छवि बना दी कि सभी पोलीटिकल लोगों को जनता ठग समझने लगी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि ये लोग जो प्रदेश का खरबों रुपया खा गये इनके खिलाफ कार्यवाही करने में सरकार के स्तर पर ढिलाई क्यों बरती जा रही है। इस प्रकार के ठग और लुटेरे लोगों को तो यहां आने की अनुमति ही नहीं होनी चाहिए। इनकी सारी की सारी जायदाद कुर्क करके इनको जेल के अन्दर डालना चाहिए। ऐसे-ऐसे ठगों की वजह से ही आम आदमी के मन में राजनीतिज्ञों की ऐसी छवि बन गई है कि सभी पोलीटिकल आदमी ठग और बदमाश होते हैं। ये तो सदन में आकर भी ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे इनके लिए न तो कोई कायदा है और न ही कोई कानून है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के नेता से यह अनुरोध करूँगा कि वे इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करें।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भ)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहूँगा कि यह बात ठीक है कि हमारी चक्की आहिस्ता पीस रही है लेकिन वह बारीक पीस रही है। इस बात की वे कोई चिंता न करें।

अध्यक्ष महोदय, यह बात मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि पहले हरियाणा प्रदेश में पानी का न्यायोचित बंटवारा नहीं था। हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इस बात का पक्का इरादा किया है कि हम अंतिम छोर तक पानी पहुँचायेंगे। जिसका जितना हक बनता है वह उसको

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

मिलेगा। इसी प्रकार से जो शाहबाद-दादुपुर-नलवी परियोजना है वह पिछले 20 वर्षों से कागजों में थी। यहां पर जितनी भी अब तक असैम्बली बनी उनमें से हरेक असैम्बली में प्रत्येक आदमी ने इस बात की चर्चा की लेकिन फिर भी 20 वर्षों तक वह कागजों में ही घूमती रही। यह कार्य भी हमारी सरकार ने शुरू किया। अध्यक्ष महोदय, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इस नहर का 68 प्रतिशत अर्थ वर्क का काम और 30 प्रतिशत पक्के स्ट्रक्चर का काम पूरा हो गया है। इस पूरी परियोजना के कम्पलीट होने पर 267 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। इसी प्रकार से ओटू झील के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने 55 करोड़ रुपये की लागत से ओटू झील की खुदाई का कार्य शुरू करवाया है और इससे सिरसा जिले में 5 हजार एकड़ भूमि की सिंचाई में लाभ होगा। इसके साथ ही साथ हम वर्ष 2008-2009 के दौरान 81 करोड़ की लागत से सभी नहरी खालों की मुरम्मत का कार्य पूरा करेंगे। इसके अलावा जो एस०वाई०एल० नहर है यह हमारी लाईफलाईन है इसके निर्माण और इसमें अपने हिस्से का पूरा पानी लाने के लिए भी हम वचनबद्ध हैं। अध्यक्ष महोदय, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले की जल्दी से जल्दी सुनवाई करने के आदेश पारित किए हैं। आज हमारे सामने सबसे अहम मसला और सबसे बड़ी समस्या बिजली की कमी की है। यह समस्या हमें विरासत में मिली है। इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि जिस प्रकार हम निरंतर विकास कर रहे हैं उसके दृष्टिगत हमारी बिजली की मांग भी दिन प्रति दिन हर साल बढ़ती जा रही है और जिस हिसाब से यह मांग बढ़ रही है उस हिसाब से बिजली के उत्पादन की व्यवस्था पिछली सरकारों ने नहीं की। मैं किसी की निन्दा करने का आदि नहीं हूँ लेकिन फिर भी मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हरियाणा प्रदेश को अस्तित्व में आये 40 साल हो गये हैं और कुछ लोग 10-10 साल यहां मुख्यमंत्री रहे लेकिन मांग के अनुसार बिजली को बढ़ाने के लिए किसी ने भी ईमानदारी से प्रयास नहीं किये। आज हम 1587 मैगावाट बिजली पैदा करते हैं और दो हजार मैगावाट के आस पास बाहर की बिजली परियोजनाओं में हमारा हिस्सा है। इस प्रकार इस समय हमारे पास कुल उपलब्ध बिजली 4051 मैगावाट या इससे कुछ अधिक है। इसीलिए जब 3 साल पहले हमारी सरकार बनी तो हमने लोगों से वायदा किया था कि हम 5000 मैगावाट और बिजली पैदा करेंगे क्योंकि वर्ष 2010 में बिजली की मांग कम से कम 8500 मैगावाट होने जा रही है। यह एक बहुत बड़ा कार्य है और इसके बिना विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बिजली विकास की धुरी है। लेकिन हमारे विपक्ष के साथी अपने चुनाव घोषणा पत्रों में यह वायदे करते थे कि फलां तारीख से हम 24 घंटे बिजली देंगे लेकिन उन द्वारा निर्धारित तारीख कभी आई ही नहीं। ऐसा करके ये सिर्फ लोगों को गुमराह करते रहे। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में आपको थोड़ा कम्पैरेटिवली बताना चाहूँगा कि वर्ष 2004-05 में 578 लाख यूनिट प्रति दिन बिजली उपलब्ध थी और उसके मुकाबले में वर्ष 2006-07 में हमने 662 लाख यूनिट प्रति दिन बिजली उपलब्ध कराई और जनवरी 2007-08 में 739 लाख यूनिट प्रति दिन बिजली हम उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके अतिरिक्त बाहर से भी बिजली की खरीद की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2003-04 में जो बिजली शार्ट टर्म प्रॉवीज़न के तहत खरीदी गई इनकी सरकार के समय में उस पर 607.15 करोड़ रुपये खर्च किये गये उसके मुकाबले वर्ष 2007-08 में हमने 1583.71 करोड़ रुपये की बिजली की खरीद बाहर से की गई। इस प्रकार से हमारी सरकार द्वारा बाहर से बिजली की खरीद में भी बड़ी भारी बढ़ोत्तरी की गई। इनकी सरकार के समय में पाँच साल में कुल 4095 करोड़ रुपये बिजली पर खर्च किये गये और

हमारी सरकार के पिछले तीन वर्षों के कार्यकाल में इस मद पर 6748 करोड़ रुपये खर्च किये गये। इसके अलावा 11वीं पंचवर्षीय योजना में सरकारी व बिजली कम्पनियों द्वारा 25,520 करोड़ रुपये बिजली के उत्पादन पर खर्च किये जायेंगे। इसी प्रकार से मैं यमुनानगर थर्मल प्लांट के बारे में बताना चाहूँगा। जैसा कि मैंने कहा कि हमारी सरकार का 5000 मैगावाट अतिरिक्त बिजली के उत्पादन का लक्ष्य है। यमुनानगर में बिजली का प्लांट लगने के बारे में भी हम सुनते रहे। आज यमुनानगर में बिजली का प्लांट लग गया है। इस प्लांट को लगाने के लिए कई बार शिलान्यास हुआ लेकिन यह काम भी हमारी सरकार ने ही शुरू किया है। इसको नवम्बर, 2007 में सिंक्रोनाइज किया गया है और मार्च, 2008 में कोयले से 300 मैगावाट की पहली यूनिट से उत्पादन शुरू हो गया है। अब तक 85 लाख यूनिट बिजली नई यूनिट से बनाई जा चुकी है और इसकी दूसरी यूनिट अप्रैल या मई, 2008 में शुरू होने वाली है। इस पर लगभग 2400 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने यमुनानगर में बिजली उत्पादन में देरी की बात कही है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को बताना चाहता हूँ कि जुलाई, 1998 में तत्कालीन बंसी लाल सरकार ने बिजलीघर लगाने की प्रक्रिया शुरु की थी। वर्ष 1999 में चौटाला जी लोगों को गुमराह करके सत्ता में आ गये और इन्होंने इसे ठण्डे बस्ते में डाल दिया। जुलाई, 1998 से 6 वर्षों के बाद 30 सितम्बर, 2004 को, चुनाव से ठीक पहले चौटाला सरकार ने रिलायन्स एनर्जी लिमिटेड को बिजलीघर निर्माण की चिट्ठी दी। 6 महीने तक कोई कार्य शुरू नहीं हुआ। हमने यह कार्य शुरू करवाया और इसे पूरा भी करवाया। इस प्रकार से सबसे कम समय में यह कार्य पूरा हुआ है। इसी प्रकार से राजीव गाँधी थर्मल प्लांट हिसार के खेदड़ में हम लगाने जा रहे हैं जिस पर 3775 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। उस पर कार्य चल रहा है। इसी प्रकार से इंदिरा गाँधी थर्मल प्लांट झाड़ली (झज्जर) में 1500 मैगावाट का प्लांट हम लगाने जा रहे हैं। उस पर 7892 करोड़ रुपये की लागत आयेगी और उस पर भी कार्य चल रहा है। उसमें 750 मैगावाट बिजली हरियाणा का हिस्सा होगा। दूसरा, झाड़ली में ही 1200 मैगावाट का प्लांट लगाने की प्रक्रिया जल्द ही पूरी कर ली जायेगी और जल्द ही उसका काम शुरू होने जा रहा है। 2000 मैगावाट बिजली की खरीद की प्रक्रिया 3 महीने में पूरी कर ली जायेगी। अमर कंटक प्रोजैक्ट-2 में से 300 मैगावाट बिजली हमें मिलेगी। इसी तरह से बुडील हाईड्रो प्रोजैक्ट से 70 मैगावाट बिजली 2010 तक हमारे को उपलब्ध हो जायेगी। राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत अब तक कुल 200 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 2,32,000 परिवारों को इसका लाभ हुआ है। नॉन कन्वैन्शनल एनर्जी पर भी हमारी सरकार का पूरा ध्यान है। 705 मैगावाट बिजली के उत्पादन का हम समझौता कर चुके हैं और 2 साल में बिजली उत्पादन की सम्भावना है और इस पर लगभग 3300 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। हमारा पूरा ध्यान बिजली उत्पादन की तरफ है। मानसून व सर्दी की बारिश न होने के बावजूद साल 2007-08 में मेरी सरकार ने 31 जनवरी, 2008 तक 217.96 करोड़ यूनिट बिजली प्रान्त को दी है जो कि पिछले साल के मुकाबले 11.14 प्रतिशत अधिक है। गैस उपलब्ध न होने के बावजूद गैस आधारित बिजलीघर के शिलान्यास के बारे में गेल द्वारा गैस सप्लाई करने के आश्वासन पर फैसला किया गया लेकिन गैस अब तक उपलब्ध नहीं हुई। गैस उपलब्ध होते ही वह कार्य शुरू हो जायेगा। एक बात और की गई और विपक्ष की तरफ से ब्यान भी आया, इन्होंने अपने भाषण में भी चण्डीगढ़ हवाई अड्डे के बारे में कहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को गर्व से कहता हूँ कि चण्डीगढ़ हरियाणा की राजधानी है और यहाँ पर मोहाली के नाम से हवाई अड्डा बनने जा रहा है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]
उस हवाई अड्डे में पंजाब हिस्सेदारी करे तो वह लाभदायक और हरियाणा हिस्सेदारी करे तो वह नुकसानदायक कैसे हो सकता है। मुझे इस बात का गर्व है कि अगर हम यह समझौता नहीं करते तो चण्डीगढ़ पर हमारा क्लेम कमजोर हो सकता था। लेकिन चौटाला जी तो चाहते हैं कि चण्डीगढ़ को पंजाब में ही मिला दिया जाये क्योंकि वहाँ उनके साथ बादल की दोस्ती है। मुझे इस बात की खुशी है कि पूरे हरियाणा में इस बात की प्रशंसा हुई कि हरियाणा ने इसमें अपना हिस्सा लिया। (इस समय मेजें थपथपाई गई) आखरी मिनटों में हमने फैसला किया कि जब तक हमारा हिस्सा तय नहीं हो जाता तब तक हम समझौता नहीं होने देंगे क्योंकि चण्डीगढ़ हरियाणा की राजधानी है। केन्द्र की टीम को हमने हवाई अड्डे पर ही रोका। इनको इस बात की निन्दा करने की बजाय प्रशंसा करनी चाहिए क्योंकि यह एक कमर्शियल प्रोजैक्ट है और इसमें हमारे को लाभ ही होगा। हरियाणा को इसका पूरा लाभ मिलेगा। यहाँ विकास होगा। हमारा प्रदेश चण्डीगढ़ के चारों तरफ है। चण्डीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनना है हम सोचते हैं कि इसमें हम साझीदार हों, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, इसमें 51% शेयर भारत सरकार का होगा जब कि 24.5% शेयर हरियाणा सरकार का और 24.5% शेयर पंजाब सरकार का होगा। इसमें पंजाब सरकार तथा हरियाणा सरकार बराबर के हिस्सेदार हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से जैसे मैंने कहा कि विकास के नाम पर गुड़गांव हमारा एक किस्म से प्रैस्टिजीयस फेस बना हुआ है और पूरी दुनिया में गुड़गांव के नाम की चर्चा है और इसको हम मैट्रो रेल सेवा से जोड़ने जा रहे हैं। मैट्रो रेल सेवा का विस्तार कार्य शुरू किया हुआ है और इस पर 1581 करोड़ रुपये खर्च करके हम मैट्रो रेल को गुड़गांव तक बनाने जा रहे हैं। यह कार्य जनवरी, 2010 तक पूरा कर लिया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से फरीदाबाद शहर तक मैट्रो रेल सेवाएं पहुँचाने की मंजूरी भी दे दी गई है और बहादुरगढ़ तक यह मैट्रो सेवा पहुँचाने के लिए हमारे प्रयास जारी हैं। अध्यक्ष महोदय, दूसरे विकास कार्यों के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाना हमारा लक्ष्य है जो कि सड़कें और पुलों से कन्सर्ड है। इनके बिना हमारा विकास नहीं हो सकता है इसलिए हमने सड़कों और पुलों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया है। वर्ष 2007-08 तक लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कें एवं भवन बनाने पर लगभग 1500 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा रही है जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पिछली सरकार ने इस राशि को औसतन अढ़ाई सौ करोड़ से 300 करोड़ तक रखा था जबकि उसके मुकाबले में हम 1500 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। पिछली सरकार ने अपने पूरे कार्यकाल में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत 100 करोड़ से भी कम खर्च किया था जबकि हमारी सरकार ने इस मद के अन्तर्गत वर्ष 2007-08 में ही 450 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार से मन्जूर करवाए हैं जिसमें से 1085 किलोमीटर लम्बी और 108 किलोमीटर सड़कों को चौड़ा व मजबूत किया जा रहा है। स्पीकर सर, हमने 28 नवम्बर, 2007 को 3000 करोड़ रुपये से राजीव गांधी ब्रिजिज एण्ड रोड डिवैल्पमैंट इन्फ्रास्ट्रक्चर की शुरुआत की है इसके अन्तर्गत हर वर्ष 1000 करोड़ रुपये इस कार्य पर खर्च करेंगे। रेलवे ओवर ब्रिजिज पर सरकार ने रिकॉर्ड काम किया है। वर्ष 1966 में हरियाणा राज्य का गठन हुआ था और वर्ष 1966 से लेकर 2005 तक केवल 16 आर०ओ०बी० का निर्माण हरियाणा में हुआ है जबकि मौजूदा सरकार के तीन साल के कार्यकाल में 4 आर०ओ०बी० तो पूरे कर लिये गये हैं और 20 आर०ओ०बी० पर 300 करोड़ रुपये की लागत से काम चालू हो रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारी सरकार के तीन साल के कार्यकाल में ही 24 आर०ओ०बी० का निर्माण कार्य शुरू हो गया है (इस समय मेजें थपथपाई गई) जब

कि 40 साल में कुल 16 आर०ओ०बी० बने हैं। अध्यक्ष महोदय, 85 पुलों के लिए 82 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की जा चुकी है और इसके साथ ही 139 पुलों का, 110 करोड़ रुपये की लागत से सुधारीकरण का कार्य किया जायेगा जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। स्पीकर सर, दिल्ली-रोहतक हाई-वे की सिक्स लेनिंग का काम शुरू है और पानीपत में ऐलिवेटिड कॉरीडोर सड़क लगभग सम्पूर्ण हो चुकी है। दिल्ली-बदरपुर फलाईओवर के काम की मन्जूरी हो चुकी है जो हमारी सरकार के लिए गौरव की बात है। अध्यक्ष महोदय, मेरे लिए यह बड़े अफसोस की बात है कि आज जो हमारा हरियाणा है इसमें किसान की जमीन बहुत ही थोड़ी रह गई है। अगर दादा के नाम पर दस एकड़ जमीन थी तो आज पोते के नाम पर केवल आधा एकड़ जमीन बची है और इस आधे एकड़ जमीन से परिवार का गुजारा नहीं हो सकता है। आज प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है और इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर पैदा करना सरकार की जिम्मेदारी है। अगर हम रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा नहीं करेंगे तो प्रदेश में अराजकता पैदा हो जायेगी। कृषि क्षेत्र में रोजगार के साधन बढ़ाने की कोई गुंजाईश नहीं रही है क्योंकि किसान आज दस एकड़ से आधा एकड़ पर पहुँच गया। यही कारण है कि हम प्रदेश में इण्डस्ट्रिलाईजेशन पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और हम एग्रो से इण्डस्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के साथियों ने बड़ी भारी चर्चा की कि सरकार ने एस०ई०जैड० के लिए जमीन ऐक्वायर की है जबकि इन्होंने खुद अपनी सरकार के कार्यकाल में सेज के लिए जमीन ऐक्वायर की थी। जब हम इण्डस्ट्रिलाईजेशन की ओर जा रहे हैं और लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए इण्डस्ट्रीज को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं तो ये लोग कह रहे हैं कि कृषि योग्य भूमि उद्योगों में जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भविष्य में अगर हमने लोगों को रोजगार देना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा इण्डस्ट्रीज लगानी पड़ेंगी और इण्डस्ट्रीज का विकास करना पड़ेगा क्योंकि सभी को सरकारी नौकरियां नहीं मिल सकेंगी यह बात सब को मालूम है। कृषि क्षेत्र में सब का गुजारा नहीं हो सकता है तो रोजगार कहां से पैदा होगा। इण्डस्ट्रीज अगर लगेंगी और कोई बड़ी यूनिट लगती है तो छोटे-छोटे कई यूनिटस लगेंगे और जो कोई काबिल बच्चा होगा वह अपना छोटा यूनिट लगाएगा और कोई बच्चा इस छोटे या बड़े यूनिट में नौकरी करेगा या अपना कोई छोटा-मोटा धन्धा करेगा। इसी प्रकार से सभी लोगों को रोजगार मिल पाएगा। दूसरे हिसाब से हमने इण्डस्ट्रीज को बढ़ावा दिया है। स्पीकर साहब, लागत में हम आज प्रथम स्थान पर हैं। हरियाणा के 40 साल के इतिहास में इण्डस्ट्रीज में कुल निवेश 40 हजार करोड़ रुपए का हुआ था और हमारी सरकार आने के बाद के तीन सालों में इण्डस्ट्रीज के अन्दर निवेश 33 हजार करोड़ रुपए ऑन ग्राउन्ड हो गया है। मुझे इस बारे में सदन में बताते हुए खुशी हो रही है। इसके साथ ही 68 हजार करोड़ रुपए का निवेश इण्डस्ट्रीज का पाईप लाईन में है। जो एस०ई०जैड० का निवेश है वह इससे अलग है। अध्यक्ष महोदय, मुझे कृषि क्षेत्र का भी ध्यान है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में बताना चाहूँगा कि हमारा यह फैसला है कि हमारी हरियाणा की जितनी भी भूमि है उसके 1 प्रतिशत पर ही इण्डस्ट्रिलाईजेशन होगी, उससे ज्यादा पर हम इण्डस्ट्रिलाईजेशन नहीं करेंगे। इससे ज्यादा पर न इण्डस्ट्रिलाईजेशन हो सकती है और न ही हम करेंगे। इस 1 प्रतिशत जमीन पर हम रोजगार के साधन भी पैदा करेंगे ताकि हमारे बच्चों को रोजगार मिल सके। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में बताना चाहूँगा कि एस०ई०जैड० में 93 प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुए थे जिसमें से 53 प्रस्तावों को भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसमें कुल 2 लाख करोड़ का इन्वैस्टमैंट अनुमानित है। इसमें 30 लाख

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

लोगों को रोजगार मिलने की सम्भावना है। इसके अलावा हम नए इण्डस्ट्रियल ईल्ड खरखौदा, रोहतक, फरीदाबाद और यमुनानगर में बना रहे हैं। हम चार आई०एम०टी० की स्थापना भी करने जा रहे हैं। इण्डियन ऑयल कारपोरेशन के द्वारा पानीपत में पैट्रो कैमिकल हब भी बना रहे हैं जिसमें कुल 35,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। वहां पर 50 हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने का भी हमें भरोसा है। इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, 1900 करोड़ रुपए की लागत से के०एम०पी०ई० एक्सप्रैस हाई-वे के बारे में भी चर्चा हुई है। इसी तरह से हम 135 किलोमीटर लम्बे इकोनौमी हब की भी बात कर रहे हैं। हम उसको नॉबेल कॉरीडोर के रूप में डिवैल्प करना चाहते हैं। इसके बारे में मैंने कहा है कि इसका कुल कम्पनसेशन 167 करोड़ रुपए उस समय किसानों का आंका गया था लेकिन आज हमने किसानों को उसके 630 करोड़ रुपए दिलवाए हैं। इस प्रोजैक्ट में हमने किसानों को लगभग 500 करोड़ रुपए का लाभ दिया है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा देश में पहला ऐसा प्रदेश है जिसने श्रमिक कल्याण के लिए अपनी श्रमिक नीति बनाई है और न्यूनतम वेजिज के रूप में 3510 रुपए प्रति माह के दिए जा रहे हैं। इसमें हम सब प्रदेशों से ऊपर हैं। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा का जहां तक सवाल है तो इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि आगे जिस प्रकार से दुनिया छोटी होती जा रही है उस हिसाब से आगे वही देश कम्पीटीशन में जाएगा जो शिक्षा में आगे होगा। अगर शिक्षा में हम पिछड़ गए तो हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य उज्ज्वल नहीं होगा। इस वास्ते शिक्षा पर हमारी सरकार खास ध्यान दे रही है। इसमें मैं यह कह सकता हूँ कि 3 सालों में हमने शिक्षा के बजट में 200 गुणा इजाफा किया है। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2004-05 में शिक्षा के लिए कुल 1622.89 करोड़ रुपए का बजट में प्रोवीजन था और उसके मुकाबले में वर्ष 2008-09 में हमारा प्रस्तावित बजट 3129 करोड़ रुपए का है। **(इस समय मेजें थपथपाई गईं।)** इसके साथ-साथ उत्तरी भारत में पहले महिला विश्व विद्यालय की स्थापना करने जा रहे हैं। विज्ञान एवं तकनीकी के विकास के लिए सर छोटूराम विज्ञान एवं तकनीकी विश्व विद्यालय मुरथल, जिला सोनीपत में स्थापना करने जा रहे हैं। राजीव गांधी एजूकेशन सिटी की स्थापना हो रही है। उसका काफी कार्य पूरा हो चुका है। यह एक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की एजूकेशन सिटी होगी। उसमें हमने एक ही बात रखी है कि वहां पर हर फील्ड के अन्तर्राष्ट्रीय स्टैण्डर्ड के इन्स्टीच्यूट आएंगे। चाहे वह मैडीकल एण्ड साईंस है, बॉयो टैक्नोलॉजी है, नैनो टैक्नोलॉजी है, चार्टिड अकाऊंटैंसी है या लॉ इंस्टीच्यूट हैं, वे ही वहां पर आएंगे। इसमें हमने एक कंडीशन रखी है कि वहां पर जितने भी बच्चे दाखिल होंगे उनमें से 25 प्रतिशत बच्चे हरियाणा के होंगे। **(इस समय मेजें थपथपाई गईं।)** उन 25 प्रतिशत बच्चों में से 5 प्रतिशत बच्चों की फुल फी कन्सैशन होगी। 10 प्रतिशत बच्चों को 50 प्रतिशत फी कन्सैशन होगी ताकि गरीबों से लेकर मिडल क्लॉस तक और अमीरों के बच्चे भी वहां पर अच्छी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारी शिक्षा का स्तर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का हो। इसी तरह से हमने हरियाणा में एजुसैट की स्थापना की है। अध्यक्ष महोदय, पूरे एशिया में हमने शिक्षा में सबसे बड़ा नैटवर्क इन्ट्रोड्यूस किया है। आज 11,000 कॉलेजिज को एजुसैट से जोड़ा गया है ताकि हमारे स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़े। हरियाणा पहला ऐसा प्रदेश है जहां स्कूलों में सैमेस्टर सिस्टम लागू किया गया है इसका हमें लाभ भी मिला है। इससे स्कूलों में बच्चों की और टीचर्ज की हाजिरी में इजाफा हुआ है। इसी तरह से नये अध्यापकों की भी भर्ती हुई है। शिक्षकों की भर्ती में 33 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं के लिए रखा गया है। इस तरह का आरक्षण करने वाला हरियाणा पहला प्रदेश है। अध्यक्ष

महोदय, जैसा मैंने पहले कहा कि तीन वर्षों में चाहे टैक्नीकल ऐजूकेशन हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हों, चाहे कोई और टैक्नीकल ऐजूकेशन हो या चाहे पोलेटैक्निक्स की बात हो, बहुत रोज़गार के साधन इस लाईन में उपलब्ध होने वाले हैं। अध्यक्ष महोदय, तीन वर्षों में 31 नये आई०टी०आईज०, 5 नये पोलेटैक्निक्स कॉलेज की स्थापना की गयी है। जब हमारी सरकार आयी थी उस समय तकनीकी संस्थाओं में सीटों की संख्या 24 हजार थी लेकिन हमारी सरकार ने तीन वर्ष में इनको बढ़ाकर 52 हजार कर दिया है और आने वाले दो सालों में हम इनकी संख्या एक लाख करना चाहते हैं। इसी तरह से रोहतक में मेडीकल कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाने का हमारी सरकार का प्रस्ताव है। अध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा जो हमारा गरीब और दबा हुआ वर्ग है, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनके सामाजिक कल्याण के लिए, सामाजिक न्याय के लिए हमने बजट में बड़ी भारी वृद्धि की है। इसके मुकाबले में अगर मैं पिछली सरकार के बजट का जिक्र करूं तो आपको जानकर हैरानगी होगी। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2003-04 में सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण के बजट में कितना प्रावधान था वह मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस दौरान 40.94 करोड़ रुपये रखे गए थे जबकि अब वर्ष 2008-09 में हमने 697 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए हैं यानी कई गुणा इसमें ज्यादा पैसा दिया गया है ताकि इसका लाभ हर वर्ग तक पहुँच सके। अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए हमने बजट में बहुत ज्यादा वृद्धि की है। वर्ष 2003-04 में इसके लिए कुल 47.40 लाख रुपये के बजट का प्रावधान था जबकि अब 2008-09 में प्रस्तावित बजट में इसको बढ़ाकर 2006.43 करोड़ रुपये करने का हमारा प्रस्ताव है। सभी अनुसूचित जातियों के परिवारों के लिए , बी०पी०एल० परिवारों के लिए , गरीब आदमियों के लिए 100-100 वर्ग गज के प्लाट्स देने का एक ऐतिहासिक निर्णय हमने किया है। अध्यक्ष महोदय, जो पहले प्लाट्स बंटे थे उनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं गांवों में जाता था तो हमने देखा कि बहुत सारे प्लाट्स ऐसे अलाट हुए थे जिनका कब्जा लोगों ने इसलिए नहीं लिया था क्योंकि कोई प्लाट बहुत गहराई में और कोई जोहड़ में काट दिया था जिसके कारण लोगों को बहुत दिक्कत हुई थी लेकिन अब हमने फैसला किया है कि जो ये सौ गज के प्लाट्स दिए जाएंगे वह पूरी तरह से डिवैल्प करके दिए जाएंगे। इनमें वहां पर पानी का भी इंतजाम होगा, सड़कें भी होंगी और बिजली भी होगी। अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति के पहली से बारहवीं तक की कक्षा में पढ़ने वाले लड़के-लड़कियों को सौ रुपये से लेकर चार सौ रुपये मासिक वजीफे देने की भी एक स्कीम है। एक से लेकर पांचवीं कक्षा तक के लड़के को सौ रुपये लड़की को 150 रुपये, पांचवीं कक्षा से लेकर आठवीं कक्षा तक के लड़के को 150 रुपये, लड़की को दो सौ रुपये देने का फैसला किया गया है। इस प्रकार से 12वीं तक के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों में शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए 280 करोड़ रुपये का एक पैकेज दिया जा रहा है। इस पैकेज में अनुसूचित जातियों के पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को किताबें और वर्क्स बुक्स मुफ्त में दी जाएंगी। इसके अलावा स्कूल की वर्दी, स्टेशनरी, जूते आदि के लिए वर्ष में एक बार वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। सरकारी पोलेटैक्निक्स, इंजीनियरिंग कॉलेज और तकनीकी संस्थाओं में अनुसूचित जाति के बच्चों की ट्यूशन फी का खर्चा भी सरकार वहन करेगी। इंदिरा गांधी पेयजल स्कीम के तहत अनुसूचित जाति के 8 लाख परिवारों को जो हरियाणा में हैं, मुफ्त में कनैक्शंज देने का फैसला किया गया है। खाली कनैक्शन ही नहीं बल्कि 200 लीटर की एक टंकी और एक टूटी भी मुफ्त में उनको देने का फैसला किया गया है। अध्यक्ष महोदय, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि अब तक तीन लाख से अधिक कनैक्शंज दिए जा चुके हैं और बाकी कनैक्शंज भी हम देने जा

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

रहे हैं। बी०पी०एल० में अनुसूचित जाति एवं टपरीवास जाति को मकान बनाने की राशि जो पहले दस हजार रुपये थी, उसको बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया गया है। इसी तरह से इनके मकानों की मरम्मत के लिए दस हजार रुपये देने का भी प्रावधान किया गया है। इसी तरह से गांवों में अनुसूचित जाति के 11 हजार कर्मचारी लगाने का भी एक ऐतिहासिक निर्णय हमने किया है और बहुत सारे कर्मचारी लग भी चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाले शहर के वार्ड को एक करोड़ रुपये का विकास अनुदान देने का फैसला भी किया गया है। 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाले गांव को मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति ग्राम योजना के तहत 50 लाख रुपये की डिवैल्पमैंट ग्रांट देने का निर्णय लिया गया है। इंदिरा प्रियदर्शिनी विवाह शगुन योजना के तहत अनुसूचित जाति के परिवारों की लड़कियों के विवाह के लिए 15 हजार रुपये का शगुन कन्यादान के रूप में देने का प्रावधान है। इससे अब तक 45339 परिवारों को लाभ हुआ है। इसके अतिरिक्त अब हमारा ध्यान आम आदमी के स्वास्थ्य की तरफ है। आमतौर पर स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ आम आदमी तक कैसे पहुँचे, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। यदि लोग स्वस्थ होंगे तो ही हमारा प्रदेश प्रगति कर सकता है। तीन वर्षों में इस मद में हमने लगभग 100 प्रतिशत वृद्धि की है। स्वास्थ्य सेवाओं में जो प्रति व्यक्ति खर्च किया जा रहा है उस मामले में हरियाणा देश में दूसरे नंबर पर है। इस समय राज्य में सात नये अस्पतालों का निर्माण, पांच नयी सी०एच०सी०, 40 पी०एच०सी० और पांच सब सैंटरों का निर्माण किया जा रहा है। रिवाड़ी, अम्बाला और यमुनानगर में ट्रोमा सैंटरों का निर्माण किया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत 740 करोड़ रुपये का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। 475 नये प्रसूति गृह स्थापित किए गए हैं जिनमें लगभग 400775 बच्चों का जन्म हुआ है। प्रसव के दौरान माता की मृत्यु दर 300 प्रति लाख से घटकर 142 प्रति लाख रह गई है। वहीं शिशु मृत्यु दर 62 प्रति हज़ार से घटकर 42 प्रति हज़ार रह गई है। स्त्री पुरुष अनुपात वर्ष 2001 के 819 की तुलना में नवम्बर, 2007 में 860 तक पहुँच गया है। इस प्रकार लड़का लड़की अनुपात को ठीक करने के लिए शुरू की गई लोकप्रिय लाडली योजना के तहत 63532 परिवारों को इसका लाभ हुआ है। महिला कल्याण के लिए हमारी सरकार ने बहुत से कार्य किए हैं। तकनीकी संस्थाओं में प्रवेश हेतु लड़कियों के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान हमने किया है। हरियाणा आवास बोर्ड द्वारा बनाए गए मकानों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण किया है। शिक्षकों की भर्ती में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। महिलाओं के नाम सम्पत्ति की रजिस्ट्री कराने पर स्टाम्प ड्यूटी में 2 प्रतिशत की छूट दी है। रक्षा बंधन पर हरियाणा रोडवेज की बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान की गई है। महिलाओं के नाम पर यदि बिजली का कनैक्शन लिया जाता है तो प्रति यूनिट पर दस पैसे छूट की सुविधा दी है। बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं। इसके अलावा विकलांग पेंशन 300 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये प्रतिमास की है। बौनों और किन्नरों को भी 300 रुपये प्रति मास पेंशन दी गई है। विधवा बहनों की पेंशन राशि 300 रुपये प्रति मास से बढ़ाकर 350 रुपये प्रति मास कर दी गई है। इसके साथ-साथ शतप्रतिशत विकलांगों और नेत्रहीनों की पेंशन राशि 300 रुपये प्रति मास से बढ़ाकर 600 रुपये प्रति मास की है। नम्बरदारों और चौकीदारों का मानदेय 500 रुपये प्रति मास से बढ़ाकर एक हजार रुपये किया गया है। नगर पालिकाओं, नगर परिषदों, पंचायती राज संस्थाओं और जिला परिषदों के सभी नुमाइंदों का पहली बार एक हजार रुपये प्रतिमास मानदेय से बढ़ाकर पांच हजार

रुपये प्रति मास किया गया है। 91 गांवों को आदर्श गांव घोषित किया है जिन पर 400 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि खर्च की जाएगी। 175 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। तीन वर्षों में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 481.59 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। शहरी क्षेत्र में गृहकर के बारे में ऐतिहासिक निर्णय सरकार ने लिया है। पिछली सरकार के समय में इस बारे में आन्दोलन हुआ था, उस समय मैं विपक्ष में था और पार्टी अध्यक्ष भी था तब मैंने कहा था कि हमारी पार्टी की सरकार आएगी तो हम इस पॉलिसी के बारे में जो ओल्ड पौलिसी होगी उसके मुताबिक विचार करेंगे। लेकिन हमने आते ही पूरा का पूरा गृहकर ही माफ कर दिया। इसके अतिरिक्त चूल्हा टैक्स को माफ करने का भी ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। 152 गांवों में 40 करोड़ रुपये की लागत से खेल स्टेडियम का निर्माण किया है ताकि गांवों में जो पोटेंशियल है वह आगे विकास करे, तरक्की करे। खेलों के मामले में प्रगति हो। बच्चों के पोषाहार की दर दो रुपये प्रति बच्चा प्रति दिन से बढ़ाकर तीन रुपये की गई है माताओं के लिए यह पोषाहार की राशि 2.5 रुपये प्रति दिन से बढ़ाकर 5 रुपये प्रति दिन की गई है। यह पूरे देश में सबसे अधिक है। मेरी सरकार को हरियाणा के प्रत्येक व्यक्ति का आशीर्वाद और सहयोग सही मायनों में चाहिए। मैं इस महान योगदान के लिए सभी सदस्यों का समर्थन मांगता हूँ। हमारे राज्यपाल महोदय ने जो यहां अभिभाषण दिया और पूरे प्रदेश में भारी विकास कार्य हुए हैं उनका यहां चित्रण किया और सरकार के बारे में जो विजन दिया है, उसका आइना दिया है। उसके लिए मैं पूरे सदन की तरफ से और प्रदेश के लोगों की तरफ से उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आखिर में मैं एक ही बात कहता हूँ—

''जिंदगी की असली उड़ान तो अभी बाकी है,
हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है
अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने,
आगे सारा आसमान अभी बाकी है।''

यह हमारा संकल्प भी है, हमारा रास्ता भी है। बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

Mr. Speaker : Question is —

That an address be presented to the Governor in the following terms :—

"That the Members of the Haryana Vidhan Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the Governor for the Address which he has been pleased to deliver to the House on the 7th March, 2008 at 2.00 P.M."

The motion was carried.

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the House is adjourned till 9.30 A.M. tomorrow, the 18th March, 2008.

*16.40 Hrs. (The Sabha then *adjourned till 9.30 A.M. on Tuesday, the 18th March, 2008).

44392–H.V.S.—H.G.P., Chd.